



Since 1995

Raja Travels & Car Bazar

Taxi Service, Air & Rail Tickets
Sale & Purchase Of Used Cars

WE VALUE YOUR CAR.

Car Wash
Car Wash
Car Wash

Contact :
9811172512, 9891041444

LOHIA NAGAR, NEW ARYA NAGAR (GHAZIABAD)

राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्पित दैनिक समाचार पत्र

आपका विश्वास हमारी पहचान

वर्ष : 3 ॥ अंक : 287 ॥ नई दिल्ली, गुरुवार, 17 सितंबर 2026 RNI.NO.DELHIN/2023/90791

manasvivani@gmail.com



8285002838

संक्षिप्त

समाचार

बिहार पंचायत चुनाव में ईबीसी आरक्षण को तैयारी

कहार-कुमहार-धानुक-लोहार-तेली समेत 122 जातियों को फायदा

पटना (एजेंसी)। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए आरक्षण का मानक जल्द तय होगा। पंचायती राज विभाग की विशेषज्ञ टीम की ओर से तैयार मानक संबंधी गाइडलाइन एक माह अंदर अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग को चला जायेगा। इसी पर आयोग पंचायत चुनाव में ईबीसी को



आरक्षण का प्रतिशत तय करने की अनुशंसा करेगा। आरक्षण के लिए त्रिस्तरीय जांच अनिवार्य है। पंचायत चुनाव में एससी-एसटी और ईबीसी (एनेक्सर-1) के लिए अधिकतम 50% ही आरक्षण देना है। पिछले दिनों अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिख कर गाइडलाइन मांगी थी। इसी पत्र के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यानी पंचायत चुनाव में ईबीसी आरक्षण का मानक जल्द तय होगा। एससी-एसटी से बचे हिस्से में ही ओबीसी को आरक्षण- जनगणना के आधार पर कुल आबादी में जितनी आबादी एससी और एसटी की होगी, इन वर्ग को उतना प्रतिशत आरक्षण देना है। इसके बाद ही ईबीसी को आरक्षण दिया जा सकेगा।

पंजाब में सचिन पायलट ने तैयार कर दी फेवरेबल पिच

अब फ्रंटफुट पर खेलेगी कांग्रेस राहुल गांधी की एंटी से पहले खेला

चंडीगढ़ (एजेंसी)। केंद्र में मोदी सरकार होने के बाद भी कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनावों में पंजाब में अपनी सरकार बनाई थी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस एक बार फिर से 2027 इसी को चेहरना चाहती है। राहुल गांधी ने इसके लिए अपने भरोसेमंद सहयोगी सचिन पायलट को पंजाब के मोर्चे पर लगाया था।



सचिन पायलट ने पहले पंजाब दौरे में ही चरणजीत सिंह चनी और राजा अमरिंदर सिंह वॉइंग को एकमंच पर लाकर संकेत दे दिए हैं कि उन्हें कम आंकने की भूल करना भारी पड़ सकता है। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। रजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर पंजाब में कांग्रेस गुटबाजी छोड़कर मंदान में उतरती है तो उसके लिए उज्जवल संभावना बन सकती है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पंजाब में बस यात्रा पर निकलना चाहते हैं।

दुर्गा पूजा में भगवा यूनiform में नजर आएंगे सुरक्षाकर्मी

बंगाल में कोलकाता पुलिस ने निकाला 89 लाख का टेंडर

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल में इस दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता पुलिस के ग्राउंड लेवल स्टाफ का लुक बिल्कुल बदलने वाला है। दशकों से चले आ रहे सफेद और नीले रंग के लुक को छोड़कर, पुलिस बल कुछ अलग में नजर आएगी। इस साल की दुर्गा पूजा के लिए भीड़ को संभालने वाले 20,000 गैर-पुलिसकर्मियों के लिए भगवा रंग की वर्दी होगी। इसके लिए सरकार ने 89 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। लालबाजार ने अस्थायी वॉलंटियर्स के



लिए 89 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। ये वॉलंटियर तृतीया से दशमी के बीच ट्रैफिक और पैदल चलने वालों को संभालने के लिए तैनात किए जाएंगे और चमकौले फुल-स्लीव टी-शर्ट और उनसे मेल खाती पीक कैप पहनेंगे। ऐसी होगी भगवा रंग की यूनiform- लालबाजार के अधिकारी ने बताया कि दो तरह के केसरिया रंग के कपड़े बनाए जा रहे हैं। कॉलर और पूरी बाजू वाले इन कपड़ों का रंग महारा केसरिया और हल्का केसरिया होगा। पुलिस ने 12,000 गहरे केसरिया और 8,000 हल्के केसरिया रंग के कपड़े डिजाइन किए हैं।

पीएम के साथ पढ़े असगर अली को वापस मिली जमीन

● महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने छोड़ा कब्जा ● आठ दिन पहले पीएम मोदी से मिलकर शिकायत की थी

भायंदर (एजेंसी)। महाराष्ट्र में ठगने के मीरा रोड में रहने वाले 81 साल के असगर अली वोहरा को जमीन विवाद में रहत मिली है। पीएम मोदी से मुलाकात के 8 दिन बाद भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने उनसे जुड़ी विवादित जमीन का कब्जा छोड़ने और कंस्ट्रक्शन परमिट सरेंज करने की बात कही है। वोहरा ने 8 सितंबर को पीएम मोदी से मुलाकात कर जमीन विवाद में दखल देने और सीबीआई जांच की मांग की थी। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थीं। वोहरा का दावा है कि उन्होंने गुजरात के वडनगर स्थित बीएन स्कूल में पीएम के साथ एक ही क्लास में पढ़ाई की थी।



● 15 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे वोहरा- वोहरा के मुताबिक, जमीन को लेकर वह करीब 15 साल से अलग-अलग

सरकारी विभागों के सामने मामला उठा रहे थे। उनका आरोप है कि उनकी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उसे दो

कंपनियों के बीच बांट दिया गया। इन कंपनियों के नाम स्वयं बिल्डर्स और सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शंस हैं। वोहरा ने दोनों कंपनियों को नरेंद्र मेहता से जुड़ा बताया था। इस मामले में 2015 में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। वोहरा के मुताबिक, पीएम से मुलाकात के बाद मामले में गतिविधियां शुरू हुईं। मीरा-भायंदर नगर निगम ने दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट को 16 सितंबर को अपना पक्ष रखने और मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया था। इससे पहले ही मंगलवार को जमीन वापस मिलने के संकेत मिल गए।

कंपनी ने निगम से कंस्ट्रक्शन परमिट रद्द करने की मांग की

बैठक के बाद सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने मामले से पूरी तरह पीछे हटने की बात कही है। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, कंपनी ने मीरा भायंदर नगर निगम के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग को लेंटर देकर प्लॉट का कर्मसमेंट सर्टिफिकेट सरेंज कर दिया। कंपनी ने बताया कि उसने 13 जून 2019 को रजिस्टर्ड डीड के जरिए प्लॉट खरीदा था और 17 अप्रैल 2026 को निर्माण की इजाजत हासिल की थी। लेकिन जमीन के मालिकाना हक के विवाद को देखते हुए कंपनी ने परमिट वापस करने का फैसला किया। उसने नगर निगम से कंस्ट्रक्शन परमिट रद्द करने और प्रोजेक्ट के लिए जमा की गई फीस वापस करने की मांग की। नरेंद्र मेहता ने पुलिस कमिश्नर को अलग लेंटर भेजा। इसमें उन्होंने वोहरा और उनके सहयोगी अजय ढोका के खिलाफ पहले की गई शिकायत वापस लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है।

पीएम का 76वां जन्मदिन आज, देशभर में कार्यक्रम

उज्जैन में 25 लाख दीप जलेंगे, फरीदाबाद में दिव्यांगों को स्कूटी

गुजरात से वाराणसी तक निकलेगी बाइक यात्रा, तैयारी हो गई पूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन कल 17 सितंबर को है। इस मौके पर भाजपा देशभर में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसे मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने से भी जोड़ा गया है। इसके तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संस्करण अभियान' चलाया जाएगा। जन्मदिन पर देश के अलग-अलग हिस्सों में सेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम होंगे। भाजपा ने लोगों से घरों में 'आशीर्वाद का दिया' जलाने की अपील की है। गुजरात स्थित पीएम के जन्मस्थल वडनगर और वाराणसी से बाइक यात्रा शुरू होगी। फरीदाबाद में दिव्यांगों को ई स्कूटी बांटेगे।



● उज्जैन में 25 लाख से ज्यादा दीप जलेंगे- उज्जैन में क्षिपा नदी के घाटी और महाकाल लोक क्षेत्र में करीब 25 लाख मिट्टी के दीप जलाए जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष नीतिन नदीन क्षिपा नदी की आरती और 'आशीर्वाद का दिया' कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी दिन इंदौर में केंद्र की स्वागत यात्रा शुरू होगी। फरीदाबाद में दिव्यांगों को ई स्कूटी बांटेगे।

● पश्चिम बंगाल में 50 हजार लाभार्थियों का कार्यक्रम- कोलकाता के बोईमेल ग्राउंड में 17 सितंबर को करीब 50 हजार अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को जुटाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करने की संभावना है। मुंबई में 10 प्रमुख जगहों को रोशन किया जाएगा। इनमें गेटवे ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं।

ईपीएफ के लिए बेसिक सेलरी लिमिट बढ़कर 25 हजार हुई

12 साल बाद बदलाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ईपीएफ और ईपीएस के लिए अनिवार्य बेसिक सेलरी लिमिट बढ़ाकर 25,000 प्रति महीना कर दी है। अब कंपनियों को 25 हजार रुपए तक की बेसिक सेलरी वाले कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में शामिल करना ही होगा। पहले यह लिमिट 15,000 प्रति महीना थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इससे 51 लाख कर्मचारियों को पीएफ बचत और पेंशन का सीधा फायदा मिलेगा। पहले 15 हजार रुपए से ज्यादा बेसिक सेलरी वाले कर्मचारियों को पीएफ कटना या न कटना उनकी मर्जी पर डिपेंड करता था। नए आदेश से पीएफ कटने से कर्मचारी की सेविंग बढ़ेगी।

अरब सागर में हादसा, दिल्ली में पाक हाई कमिश्नर तलब भारतीय युद्धपोत से टकराया पाकिस्तानी नेवी शिप

15 साल पहले भी टकराए थे भारतीय-पाकिस्तानी वॉरशिप

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जहाज से टकरा गया। घटना कब की है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले 2011 में भी दोनों देशों के जहाजों में टक्कर हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय युद्धपोत नियमित निगरानी मिशन पर था। इसी दौरान पाकिस्तानी जहाज तेज रफ्तार में आया और गलत दिशा में मुड़ गया, जिससे दोनों जहाज टकरा गए। सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी जहाज का नाम पीएनएस हुनेन है। इसे समुद्री निगरानी और गरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टक्कर में इसको



नुकसान पहुंचा है। हालांकि, भारतीय नौसेना के जिस जहाज से इसकी टक्कर हुई, पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमिशन के चार्ज डी ऑफेयर्स को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने घटना को अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर बताया।

मुसलमानों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म-जन्म का साथ नहीं

● असदुद्दीन ओवैसी के पांच पंच से गोलबंद होंगे एमपी के मुसलमान! ● यूसीसी के बहाने एमपी के मुसलमानों को गोलबंद करने में जुटे ओवैसी

भोपाल (एजेंसी)। यूसीसी को खिलाफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भोपाल आकर माहौल बना दिया है। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे थे। ओवैसी ने कहा कि यूसीसी का कानून सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट को गैर हिंदुओं पर थोपा जा रहा है। ओवैसी ने अपनी रैली में कई ऐसी बातें कही हैं, 2028 के लिए बड़ा मैसैज है। उन्होंने पूछा कि हम बीजेपी से

पूछना चाहता है कि यूसीसी से आदिवासियों को अलग क्यों किया। उनका जवाब होगा कि उनके तौर-तरीके अलग हैं। मैं पूछना चाहता कि क्या मुसलमानों का मजहब अलग नहीं है। जमीरफरोश लोगों ने जालिमों के सामने घुटने टेक दिए हैं। भारत की संविधान में प्रीडम ऑफ रिलीजन है। एमपी की यूसीसी तमाम फंडमेंटल राइट्स के खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदू समाज में शादी जन्म-जन्म का साथ होता है। मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है, मुस्लिमों में

शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर निक्काह किया जाता है। बीजेपी यह बताना चाहती है कि



मुसलमानों में जन्म-जन्म का साथ होता है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि हमारे यहां एडोप्शन नहीं होता है। बीजेपी ने

तमाम चीजों को हिंदू मैरिज एक्ट से लाया है। बीजेपी मुसलमानों को मजहब से दूर करना चाहती है। मस्जिदों से दूर

हम मुसलमान बनकर भारत में जाँएंगे- इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि हम भारत में मुसलमान बनकर जिएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर की संविधान हमें इजाजत देता है कि हम शरीयत के आधार पर चलें। बीजेपी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी शरीयत को खत्म कर दें। मध्य प्रदेश में कई मुस्लिम नेता हैं, लेकिन ओवैसी की तरह बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ललकार नहीं पाए। काजी कैप वाले बयान को लेकर ने खुले मंच से बीजेपी विधायक को ललकारा है।

एमपी के मुसलमानों को गोलबंद करेंगे ओवैसी

यूसीसी के मसले पर फूटकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा संदेश दिया है। वह इसके जरिए मुस्लिमों को एकजुट करने में जुटे हैं। राजधानी भोपाल में दो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। दोनों पर पचीं से कांग्रेस का कब्जा है। यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस ओवैसी की तरह खुलकर सामने नहीं आई है। ऐसे में मुस्लिम समाज अपना भविष्य देख रहे हैं। कांग्रेस विधायकों को छोड़ दें, पार्टी मुखर होकर मुस्लिमों की बात नहीं रखती है। ओवैसी ने मंच से यह भी कहा कि भाइयों जाए तुम्हारा यूनियन में मिलिल कोड। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 2022 के निकाय चुनाव में ओवैसी का खाता खुल चुका है। जुलाई 2022 में हुए निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी के दो पार्षद जबलपुर और एक खडवा में जीते थे। यूसीसी को लेकर मुसलमानों में आह्वान है, उसे अब ओवैसी कैश करवाने में जुटे हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी को एमपी में कोई सफलता नहीं मिली थी।

ब्रिक्स बैठक में मोदी का संदेश, आपसी हित और सम्मान से आगे बढ़ें भारत-चीन

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन को एक-दूसरे की मूल वित्ताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी सहमति से निर्देशित होना चाहिए। जब बैठक को लेकर चीनी पक्ष के बयान के बारे में पूछा गया, जिसमें कहा गया था कि तड़पावन और तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर भारत की नीति और स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और वह



अपनी धरती पर किसी भी ताकत को चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा, तो जायसवाल ने जवाब दिया, "चर्चा के दौरान कई मुद्दों सामने आए, और हमने आपको उनसे अवगत कराया है, जिनमें आपके सवाल में उल्लिखित मुद्दे भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने भारतीय वित्ताओं का भी जिक्र किया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की मूल वित्ताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन आपसी सिद्धांतों- आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता से निर्देशित होना चाहिए। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने 12 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक की, जहां दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि "मनभेदों को विवाद नहीं बनना चाहिए" और इस बात की पुष्टि की कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, "दोनों नेताओं ने अगस्त 2025 में तियानजिन में अपनी द्विपक्षीय बैठक के बाद से भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में स्थिर प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने पुष्टि की कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मनभेदों को विवाद नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों पक्षों को तीन आपसी सिद्धांतों- आपसी

सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित से निर्देशित होना चाहिए।" बैठक के दौरान पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए एक आवश्यक आधार बनी हुई है। विदेश मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया, "उन्होंने दोनों पक्षों की ओर से सीमा से जुड़े मुद्दों पर मौजूदा समझौतों और सहमतियों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने अपने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और दोनों देशों के लोगों के दीर्घकालिक हितों के आधार पर सीमा प्रश्न के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।" दोनों नेताओं ने लोगों के बीच आपसी संबंधों में हुई प्रगति पर भी गौर किया और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक

आशा कार्यकर्ताओं को दिल्ली में अब तीन हजार की जगह मिलेंगे, छह हजार रुपये

नई दिल्ली। देश की राजधानी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के मासिक प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब उन्हें प्रति माह तीन हजार रुपये की जगह सीधे छह हजार रुपये मिलेंगे। यह बुद्धि दिल्ली में कार्यरत सभी आशा कार्यकर्ताओं पर लागू होगी। हालांकि अन्य प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि आशा कार्यकर्ता दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे घर-घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती हैं, परिवारों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करती हैं तथा गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं की देखभाल से संबंधित सेवाओं में सहयोग करती हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण विभाग, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों, सर्वेक्षणों और सामुदायिक बैठकों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कोरोना महामारी के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की थीं। दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। एक आशा कार्यकर्ता लगभग दो हजार लोगों या 4 सौ परिवारों से जुड़ी होती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन में बुद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान के सम्मान के साथ-साथ उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उनके कार्य के प्रति उत्साह और सेवा निरंतरता को बल मिलेगा।



एक्सप्लेनर: नए यूपीए फ्रेमवर्क में पी2पी लेनदेन पर नहीं लगेगा चार्ज, ग्राहकों को जारी रहेगी छूट

नई दिल्ली। नए यूपीआई फ्रेमवर्क से किसी भी पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) लेनदेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के लेनदेन को एमडीआर ढांचे से बाहर रखा गया है। यह जानकारी मंगलवार को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक्सप्लेनर में दी गई। एक्सप्लेनर में बताया गया कि नए यूपीआई ढांचे के तहत 2,000 रुपये तक के व्यापारियों को किए जाने वाले भुगतान के साथ-साथ छोटे व्यापारियों के लिए जीरो-एमडीआर फ्रेमवर्क के तहत आने वाले लेनदेन भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप, सभी पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन में लगभग 96 प्रतिशत लेनदेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमडीआर केवल 2,000 रुपये से अधिक के पीएम लेनदेन पर लागू होगा।



यह व्यापारिक शुल्क पर लगेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एमडीआर न तो कोई टैक्स है और न ही सरकार या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क है। इसे यूपीआई इकोसिस्टम के संचालन और निरंतर विस्तार में सहायता के लिए बैंकों और पेमेंट एंजलेशन प्रदाताओं सहित भुगतान इकोसिस्टम के प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाएगा। 0.4 प्रतिशत का मामूली एमडीआर केवल 2,000 रुपये से अधिक के पी2एम लेनदेन पर लागू होगा। एमडीआर को बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई एंजलेशन प्रोवाइडर्स सहित भुगतान इकोसिस्टम के प्रतिभागियों के बीच साझा किया जाएगा। 75,000 रुपये और उससे अधिक के लेनदेन के लिए एमडीआर प्रति लेनदेन अधिकतम 300 रुपये होगा। रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट सहित आवश्यक और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रति लेनदेन 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर लगेगा। यह फ्लैट शुल्क महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं और कम मार्जिन पर काम करने वाले कारोबारों के लिए लागत की निश्चितता प्रदान करेगा। म्यूचुअल फंड, सिक्वेरिटीज, स्टॉकब्रोकर और डीलरों से संबंधित भुगतानों पर 0.02 प्रतिशत का एमडीआर लगेगा, जो प्रति लेनदेन अधिकतम 300 रुपये होगा। कम दर का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय बाजारों में खुदरा भागीदारी को जारी रखने में मदद करना है। एमडीआर व्यापारी भुगतान इकोसिस्टम के भीतर लिया जाने वाला शुल्क है। यह यूपीआई भुगतान करने वाले ग्राहकों पर लगाया जाने वाला शुल्क नहीं है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि व्यापारी एमडीआर शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। यूपीआई एंजलेशन प्रोवाइडर्स को प्लेटफॉर्म फीस या फिने हुए शुल्क लगाने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बैंकों और एनपीसीआई द्वारा निर्धारित दैनिक लेनदेन सीमाएं (आमतौर पर लेनदेन की श्रेणी के आधार पर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक होती हैं) सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के उपाय हैं। ये शुल्क लगाने की सीमाएं नहीं हैं। यह फ्रेमवर्क आम लोगों, सूक्ष्म उद्यमों और छोटे कारोबारों की सुरक्षा करता है, जबकि बड़े व्यापारी लेनदेन पर सीमित शुल्क लागू करता है। छोटे व्यापारियों के बीच यूपीआई को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित फंड स्थापित किया जाएगा। कुल एमडीआर संग्रह के 5 प्रतिशत के बराबर राशि इस फंड में योगदान की जाएगी। यह फंड यूपीआई की व्यापक स्वीकार्यता, निरंतर उपयोग और भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में छोटे कारोबारों के समावेशन में सहायता करेगा। एक्सप्लेनर में कहा गया है कि बड़े व्यापारी लेनदेन से उत्पन्न राजस्व बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई एंजलेशन प्रोवाइडर्स को भुगतान बुनियादी ढांचे के विस्तार और सुधार में सहायता करेगा, जिसमें ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं।

भविष्य की जंग तकनीक से जीती जाएगी, नवाचार जरूरी: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समेत सभी क्षेत्रों में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर और नवाचार को प्रोत्साहित कर भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत कर सकता है तथा भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है। राजनाथ सिंह ने टेक्नोलॉजी को 21वीं सदी के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक बताते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी में देश का भविष्य गढ़ने और उसे आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है। उन्होंने ये बातें मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित डीआरडीओ-ईडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए कही। इस कार्यक्रम की थीम वार्ता से विकास रखी गई थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में रक्षा क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स की नई लहर उभर रही है। ड्रोन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ये स्टार्टअप्स आधुनिक रक्षा परिदृश्य को नई दिशा दे रहे हैं। आज का नवाचार कल की सेन्य क्षमता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश आज नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी होगा, वह भविष्य के युद्धों में रणनीतिक बढ़त हासिल करेगा। राजनाथ सिंह ने युवाओं से आत्मविकास और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा कि जिस देश के पास अपनी तकनीक होती है, वह अपने भविष्य को स्वयं आकार देने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा, 'हम भारत के स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, नवाचार के नए ध्वजवाहक बनकर उभरें हैं।



कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ब्रिक्स डिनर का किया बहिष्कार: सबित पात्रा



नई दिल्ली। भाजपा के सांसद सबित पात्रा ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान आयोजित राष्ट्रभोज में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गैरमौजूदगी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय बैठक किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं होती, बल्कि यह देश के गौरव, विकास और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका से जुड़ा आयोजन है। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के डिनर में शामिल नहीं होने से गलत संदेश गया है और इससे कांग्रेस की दलगत राजनीति की मानसिकता सामने आती है।

सबित पात्रा ने कहा कि हाल ही में ब्रिक्स की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत ने मेजबानी की। इस दौरान पूरी दुनिया ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और देश की छवि को देखा। ब्रिक्स सदस्यों के राष्ट्राध्यक्षों का भारत आना देश के लिए महत्वपूर्ण अवसर था। ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होती है और विभिन्न देशों के साथ संवाद तथा सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं। इस तरह के आयोजन को किसी राजनीतिक दल को बैठक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ब्रिक्स का उद्देश्य भारत और अन्य सदस्य देशों के बीच सहयोग तथा वैश्विक स्तर पर साझा मुद्दों पर अग्र बढ़ना है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि ब्रिक्स से जुड़े राष्ट्रभोज के लिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। निमंत्रण में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी सम्मानपूर्वक निमंत्रण भेजा गया था। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. जगन मोहन रेड्डी का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी ओर से 12 तारीख को कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि भी भेजी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने डिनर में शामिल होने में असमर्थता जताई। पात्रा ने कहा कि केरल और कर्नाटक से जुड़े कांग्रेस नेताओं की भी राष्ट्रभोज में गैरमौजूदगी रही। उन्होंने इसे लेकर सवाल उठाया कि यदि यह राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम था तो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल होना चाहिए था। सबित पात्रा ने कहा कि ब्रिक्स की बैठक को कांग्रेस या भाजपा के चरम से देखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह देश की प्रतिष्ठा और विकास से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच है। ऐसे अवसरों पर अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े नेताओं के बीच संवाद का अवसर मिलता है। राष्ट्रभोज जैसे कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक बातचीत भी होती है। ऐसे मंच पर यह महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि कौन किस राजनीतिक दल से संबंधित है। प्राथमिकता भारत के हित, विकास और वैश्विक स्तर पर देश की भूमिका को मजबूत करना होना चाहिए। भाजपा सांसद ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गैरमौजूदगी को एक तरह का बहिष्कार बताते हुए कहा कि इससे देश के लोगों के बीच गलत संदेश जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अभी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठने की मानसिकता विकसित नहीं कर पाई है। ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच से जुड़े आयोजन में राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर देशहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक छवि से जुड़े कार्यक्रमों में सभी राजनीतिक दलों को सहयोग की भावना के साथ आगे आना चाहिए। ऐसे आयोजनों में भागीदारी देश की एकजुटता का संदेश भी देती है।

सबित पात्रा ने इस मुद्दे को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जोड़ते हुए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भले ही मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी का वास्तविक राजनीतिक नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीतिक सोच दलगत विरोध से ऊपर नहीं उठ पा रही है। उन्होंने कांग्रेस से अपनी राजनीतिक शैली में बदलाव लाने की अपील करते हुए कहा कि केवल राजनीतिक मतभेदों के कारण राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों से दूरी बनाना उचित नहीं है।

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने संगठनात्मक बैठक में कार्यकर्ताओं को दिया सेवा व समर्पण का मंत्र

नई दिल्ली। राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा का जिला केशवपुरम से एक दिवसीय संगठनात्मक एवं अध्यक्षीय प्रवास पर रहा। इस महत्वपूर्ण प्रवास के दौरान आयोजित संगठनात्मक बैठक में जिले के अग्रणी आने वाले राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला टीम, मंडल अध्यक्ष, सभी विधायकगण और निगम पार्षद प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।



यह विशेष बैठक सुबह साढ़े 11 बजे शुरू होकर शाम साढ़े पांच बजे तक चली, जिसमें विभिन्न सत्रों के माध्यम से अलग-अलग श्रेणियों

में गहन चर्चा की गई। बैठक में जिला संगठन के सरचनात्मक एवं कार्यात्मक विषयों का सुझाव से अवलोकन किया गया। साथ ही, पार्टी द्वारा वर्तमान में चलए गए बड़े अभियानों और आने वाले आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा पर गंभीर समीक्षा की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे केंद्र सरकार की जन-हितैषी और कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली के अंतिम पायदान पर छोड़ें व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निरंतर जनसेवा में समर्पित है और जनता के प्रति अपनी



नई दिल्ली। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने मंगलवार को एलांन किया कि उसने चुनिंदा यूपीआई लेनदेन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) फ्रेमवर्क में बदलाव किया है। इसके तहत, 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर चार्ज लगेगा, जबकि छोटे व्यापारियों और कम वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन के लिए जीरो एमडीआर जारी रहेगा। यह एमडीआर फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा, जबकि ग्राहकों के लिए यूपीआई लेनदेन मुफ्त बने रहेंगे। इसमें 2,000 रुपये तक के पेमेंट वाले कम-वैल्यू वाले यूपीआई पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम)

लेनदेन को एमडीआर के दायरे से बाहर रखा गया है। नए नियम के तहत, 2,000 रुपये से ज्यादा के खास पीएम यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत का एमडीआर लगेगा। एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति लेनदेन होगी। रेलवे, टेलीकॉम सर्विस, इंधन से

और पब्लि जैसी चुनिंदा मर्चेंट कैटेगरी में 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर 5 रुपये प्रति लेनदेन का प्लैट एमडीआर लगेगा। पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) यूपीआई लेनदेन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे और 2,000 रुपये तक के पी2एम लेनदेन भी एमडीआर फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर रहेंगे। इसका मतलब है कि ग्राहक बिना कोई लेनदेन चार्ज दिए यूपीआई का इस्तेमाल करते रहेंगे। पर्सन-टू-पर्सन मर्चेंट (पी2पीएम) फ्रेमवर्क के तहत काम करने वाले छोटे व्यापारियों को जीरो एमडीआर का फायदा मिलता रहेगा। इस कैटेगरी में वे छोटे वेंडर शामिल हैं जो यूपीआई

एमसीडी में भ्रष्टाचार, सेवानिवृत्त कर्मचारी से बिलिंग के नाम पर स्थित मांगने का आरोप

हरिश्चंद्र और संजय को रंगे हाथ दबोचा

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शहदरा ईस्ट जोन, जो पहले शहदरा साउथ जोन में एंटी करप्शन ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एंटी करप्शन टीम ने डेम्स विभाग से जुड़े हरिश्चंद्र और संजय नामक दो कर्मचारियों को कथित तौर पर स्थित लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर आरोप है कि दोनों एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से बिलिंग का काम करने के नाम पर स्थित की मांग कर रहे थे (एसीबी) की इस कार्रवाई ने एक बार फिर दिल्ली नगर निगम की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रणजित निगम के अलग-अलग विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप और कार्रवाई सम्प्र-समय पर सामने आती रही है, लेकिन इसके बावजूद यदि कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर स्थित मांगे का



सिलसिला जारी है तो सवाल ये भी है कि आखिर निगम के भीतर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है। ऐसे में मामले सामने आने के बाद अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों की जानकारी नहीं थी, क्या शिकायती और भ्रष्टाचार के मामलों पर विभागीय स्तर पर प्रभावी निगरानी की जा रही है। यदि (एसीबी) को कार्रवाई

करनी पड़ रही है, तो निगम की अपनी निगरानी व्यवस्था आखिर कितनी प्रभावी है। वहीं (एसीबी) की कार्रवाई के बाद पूरे मामले की जांच अहम हो गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि स्थित की कथित मांग किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में की गई थी, तथा इस प्रकरण में कोई अन्य व्यक्ति या अधिकारी शामिल था या नहीं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों को खिलफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बावजूद ऐसे मामले सामने आना निगम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई के बाद केवल दो कर्मचारियों की गिरफ्तारी तक मामला सीमित रहता है या फिर पूरे मामले की तह तक जाकर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

नीथू आजाद मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत, कोर्ट ने लगाई कड़ी शर्तें

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को नीथू आजाद मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस बात को ध्यान में रखा गया है कि आरोपी दस दिन से अधिक समय से करस्टडी में है और यह ऐसा समय था जिसमें उसे खोलने-समझने का पर्याप्त मौका मिला है। उसकी करस्टडी में पूछताछ पूरी हो चुकी है और इन अपराधों में ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा हो सकती है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उसकी मुख्य चिता शिकायत करने वाले और उसकी नाबालिग बेटी की सुरक्षा को लेकर है। इसलिए आरोपी को कड़ी शर्तों पर तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत के दौरान आरोपी के व्यवहार को देखा जाएगा और उसके बाद ही उसकी रेगुलर जमानत की जांच होगी। आरोपी को 25 घंटे की पोलिस स्टेशन मीडिया, अर्जी पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 23 जून की घटना के बारे में जो भी फैसला होगा, वह कोर्ट में सबूतों के आधार पर होना चाहिए, न कि पब्लिक में या सोशल मीडिया के आधार पर। पटियाला हाउस



कोर्ट ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक श्योरिटी के साथ तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने पांच कड़ी शर्तें लगाई हैं। पहली है कि आरोपी शिकायतकर्ता और उसके परिवार के बारे में कोई भी बयान, कमेंट, वीडियो, पॉडकास्ट, इंटरव्यू, रील या पोस्ट सोशल मीडिया, जर्नलिस्टिक या प्रिंट मीडिया या किसी दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाएगा, पब्लिश, पोस्ट, अपलोड या शेयर नहीं करेगा। दूसरी शर्त है कि आरोपी प्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ता, उसकी नाबालिग बेटी, उसके परिवार के किसी सदस्य या अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क नहीं करेगा। तीसरी शर्त है कि आरोपी इस मामले से जुड़े किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या सोशल मीडिया सामग्री सहित किसी भी खूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। चौथी शर्त है कि आरोपी को जब भी जांच अधिकारी द्वारा पूछ सुनाया पर बोलना होगा, उसे जांच में शामिल होना होगा। वहीं, पांचवी शर्त है कि आरोपी को अपना दिल्ली का पता, अपना स्थायी पता और अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी और कोर्ट को देना होगा। वह उस मोबाइल नंबर को चालू रखेगा और जांच अधिकारी को सुविधा दिए बिना नंबर नहीं बदलेगा। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को करेगी, जिसमें उसकी रेगुलर जमानत पर विचार किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने जांच एजेंसी को तेजी से जांच करने का निर्देश दिया है और कहा है कि 23 जून को जंतर-मंतर पर विशेष रूप से घटनास्थल पर या उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज एकत्र और संरक्षित किए जाएं।

निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पारदर्शिता और विश्वास स्तर पर त्वरित कदम उठाए जाएं और जमीनी स्तर पर पार्टी की फकड़ को और अधिक मजबूत किया जाए। इस अवसर पर नवयुक्त जिला अध्यक्ष एडवोकेट अजय खटना की अध्यक्षता में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जांती चौक लोकसभा प्रभारी श्री राजेश भाटिया, जिला केशवपुरम के प्रभारी श्रीमती रिवा पांडे मिश्रा, सह प्रभारी मनोज त्यागी सहित जिले के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और सेकंड्री ऊजावन कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का पुरजोर संकल्प लिया।

इस अवसर पर नवयुक्त जिला अध्यक्ष एडवोकेट अजय खटना की अध्यक्षता में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जांती चौक लोकसभा प्रभारी श्री राजेश भाटिया, जिला केशवपुरम के प्रभारी श्रीमती रिवा पांडे मिश्रा, सह प्रभारी मनोज त्यागी सहित जिले के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और सेकंड्री ऊजावन कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का पुरजोर संकल्प लिया।

संक्षिप्त डायरी

सेमीकंडक्टर के ग्लोबल मंच पर यूपी की दस्तक, 17 से 19 सितंबर तक सेमीकॉन इंडिया 2026 का दिल्ली में आयोजन

एजेंसी लखनऊ। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अपनी बढ़ती क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने जा रहा है। सेमीकॉन इंडिया 2026 का आयोजन 17 से 19 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली के यशोभूमि (आईआईसीसी) द्वारा में होगा। इसमें योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के उपरते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, नीतिगत सहयोग और भविष्य की तैयारियों को प्रमुखता से सामने रखेगी। कार्यक्रम में दुनिया के सेमीकंडक्टर कंपनियों, विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, भारतीय उद्योग जगत, स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े अन्य पक्षों की भागीदारी होगी। यूपी के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की होगी प्रस्तुति सेमीकॉन इंडिया 2026 में उत्तर प्रदेश की ओर से ऐसे प्रचार वॉइसों तैयार किए जाने की योजना है, जिनमें प्रदेश के उधरते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को दिखाया जाएगा। इसमें मौजूदा बुनियादी ढांचे, नीतिगत सहयोग और भविष्य की तैयारियों को सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही यूपी को भारत के बड़े और तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में एक प्रमुख स्थान रखने वाले राज्य के रूप में प्रस्तुत करने पर भी जोर रहेगा। आयोजन का मुख्य विषय ट्रांसफॉर्म टुरासोइसिलिकॉन टू सिस्टम्स: ब्रिलिंग ग्लोबल सफाई चैस रहेगा। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन पर चर्चा और प्रदर्शन किया जाएगा। 500 से ज्यादा प्रदर्शक, 10 राज्य पवेलियन सेमीकॉन इंडिया 2026 में 500 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे। करीब 2 लाख वर्गफुट क्षेत्र में प्रदर्शनी होगी। कार्यक्रम में 10 स्टेट पवेलियन और 7 कंट्री पवेलियन भी होंगे। इसके अलावा 40 स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप पवेलियन तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में 150 से अधिक वक्ताओं की भागीदारी, राज्य सरकारों के राउंडटेबल, प्रशिक्षण सत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंपोनेंट्स पर अलग ट्रैक और कंट्री राउंडटेबल भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें अलग-अलग राज्य, कंपनियों और वैश्विक भागीदारों के बीच संवाद का अवसर मिलेगा। यूपी में निवेश और भविष्य की तैयारी पर फोकस प्रदेश की भागीदारी का एक प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को व्यापक स्तर पर सामने रखना है। इसके तहत राज्य की मौजूदा सुविधाओं, नीतिगत समर्थन और भविष्य की तैयारियों की जानकारी दी जाएगी। ग्लोबल कंपनियों और राज्यों के बीच संवाद सेमीकॉन इंडिया 2026 में सेमीकंडक्टर उद्योग की बदलती जरूरतों, निवेश, तकनीक, सफाई चैन और भविष्य के कार्यबल से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी। आयोजन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा है। साथ ही भविष्य के लिए तैयार कार्यक्रम विकसित करने को भी कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। माफिया की तरह समाप्त हो गया इस्तेफेलाइटिस : मुख्यमंत्री

आईएमए गोरखपुर के चैरिटेबल ब्लड बैंक का सीएम योगी ने किया उद्घाटन

एजेंसी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साढ़े नौ वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस्तेफेलाइटिस से तहपते बच्चों और दम तोड़ते बचपन को देखकर हर जागरूक माता-पिता चिंतित रहता था। पर, अब यह चिंता खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि माफिया और मच्छर की तरह इस्तेफेलाइटिस भी समाप्त हो गया है। अब हम नए युग में नए गोरखपुर और नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में दस-दस बेड की डायलिसिस यूनिट की सुविधा शुरू कर रही है। सीएम योगी बुधवार पूर्वाह्न इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) गोरखपुर की तरफ से संचालित चैरिटेबल ब्लड बैंक के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने फीता काटकर चैरिटेबल ब्लड सेंटर का उद्घाटन किया और सेंटर का ध्यान कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, उपकरणों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उद्घाटन समारोह के मंच से पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में आए सकारात्मक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े नौ वर्ष पहले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमुख केंद्र था। स्थिति यह थी कि एक ही बेड पर चार-चार गरीज तक गर्त रहते थे। तीसरी मंजिल पर इस्तेफेलाइटिस वाद और वहां पंखे, शौचालय एवं अन्य जरूरी सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने कहा कि पहले जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं अस्वस्थ था, आज वहां सुपर स्पेशियलिटी सेंटर और इस्तेफेलाइटिस समेत विभिन्न बीमारियों के उपचार का प्रमुख केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में एम्स भी स्थापित हो चुका है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मिर्जागंज, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या और अंबेडकरनगर संगत विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। प्रदेश में 75 जिले हैं, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 85 हो गई है। दो एम्स भी संचालित हैं। एम्बीबीएस की सीटें 4600 से बढ़कर 13500 से अधिक हो चुकी हैं और पीजी की सीटें दोगुनी हुई हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया जा रहा है। कभी दुर्घात माफिया थे जिलों की पहचान, डॉक्टर उनके शिकार बनते थे। गोरखपुर में डॉक्टरों का अपहरण होता था, उनसे रंगदारी मांगी जाती थी, धमकी भरे फोन आते थे और उनके चैंबर में घुसकर मारपीट की जाती थी। इन घटनाओं के खिलाफ उन्हें चिकित्सकों के साथ सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर के साथ पूरे प्रदेश में चिकित्सक, व्यापारी और नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं बल्कि 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' के लक्ष्य से बन रही है। बनाया नहीं जा सकता खुन, रक्तदान सवेदना का प्रतीक रक्तदान के महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, दवाएं और संसाधन तो उपलब्ध कराए जा सकते हैं लेकिन खून बनाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि रक्तदान उस संवेदना का प्रतीक है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति किसी जरूरतमंद को नया जीवन देता है। उन्होंने इस बात पर चिंता भी जाहिर की कि रक्त की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पाती है। सीएम ने कहा कि इसके लिए चिकित्सकों को तैयिच्छ रक्तदान के प्रति लोगों को प्रेरित करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर समय-समय पर रक्तदान की अपील और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। पेशेवर रक्तदाताओं पर प्रभावी अंकुश जरूरी सीएम योगी ने पेशेवर रक्तदाताओं को लेकर भी आगाह किया। कहा कि विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त पेशेवर रक्तदाताओं पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाया गया तो संक्रमण का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। ऐसी गतिविधियों को शासन-प्रशासन के संत्रान में लाने के साथ चिकित्सकों को जागरूकता कार्यक्रमों से भी जुड़ना चाहिए। आईएमए के सामाजिक सरोकारों की सराहना की सीएम ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने आईएमए के सामाजिक सरोकारों की मुकदंठ से सराहना की। कहा कि आईएमए केवल प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों की संस्था मात्र ही नहीं है। इसने गोरखपुर में निशुल्क ओपीडी के बाद चैरिटेबल ब्लड सेंटर शुरू करके उसने सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी संस्था की वास्तविक पहचान इससे होती है कि वह अपने विशेषज्ञता का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में कितना योगदान देती है। उन्होंने कहा कि 2017-18 में गोरखपुर के सीतापुर आई हॉस्पिटल में आईएमए ने निशुल्क ओपीडी शुरू की थी। इसके बाद आईएमए ने अपने कार्यालय के लिए भूमि मांगी तो गोरखपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूछंड उपलब्ध कराने में मदद की गई। आईएमए ने इस भूखंड का बेहतर उपयोग करते हुए चैरिटेबल ब्लड सेंटर स्थापित किया है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जरूरतमंद मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने में योगदान देगा।

पंचायत सहायकों को मुख्यमंत्री योगी की बड़ी सौगात, मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी

एजेंसी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को बड़ी सौगात दी है। उनके मानदेय में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अभी पंचायत सहायकों को छह हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जाएगा। इस तरह मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही पंचायत सहायकों को सेवा सुरक्षा, कैंसलेशन उपचार और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी मिलेगी। पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्हें बुलाया। इसके बाद प्रतिनिधियों को मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत सहायकों के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। अभी पंचायत सहायकों का मानदेय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से दिया जाता है। अब कैबिनेट से स्वीकृति लेकर



डीबीटी की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके बाद नौ हजार रुपये का मानदेय सीधे पंचायत सहायकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसका लाभ प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को मिलेगा। प्रधान-सचिव नहीं हटा संकेत पंचायत सहायक



पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब ग्राम प्रधान और पंचायत सहायकों के खिलाफ पंचायत सहायक को नहीं हटा संकेत। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। किसी पंचायत सहायक को

बहाल किया जाएगा। महिलाओं को मातृत्व अवकाश, कैंसलेशन इलाज महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पंचायत सहायकों को उपचार के लिए कैंसलेशन सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा। मंत्री से वार्ता के बाद धरना समाप्त अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पंचायत सहायकों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों से पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बातचीत की। प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके साथ वार्ता की गई। इसके बाद पंचायत सहायकों के प्रतिनिधि मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर लिए गए फैसलों की जानकारी मिलने के बाद पंचायत सहायकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।

लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर युवती को कार के बोनट पर बैठाया, फिर टक्कर मारकर भागा



एजेंसी लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर चार के पास बुधवार सुबह एक युवती को कार से टक्कर मारकर भागने का मामला सामने आया है। युवती ने पुलिस को दी जानकारी में अपने परिचित युवक पर कार से टक्कर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, युवती ने बताया कि वह शहराजगंज अरुं के साथ रिलेशनशिप में थीं। बुधवार सुबह वह जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर चार के पास पास थीं। इसी दौरान शहनाज अली अपने दोस्त दानिश और दो अन्य युवकों के साथ कार से वहां पहुंची। युवती का आरोप है कि अन्य युवकों के साथ संबंधों को लेकर विरोध करने पर शहनाज और दानिश ने उससे विवाद और गल्ल-गल्ल की। इसके बाद दोनों कार लेकर जाने लगे। युवती ने कार रोकने का प्रयास किया तो आरोप है कि शहनाज ने उस कार से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा।

राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में बसपा 19 सीटों पर जीती, मायावती ने कहा -गड़बड़ी न होती और सीटें जीतते



एजेंसी लखनऊ। राजस्थान में हुए नगरीय निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को 19 सीटों पर जीत मिली है। इस जीत पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सभी पार्टी के बधाई दी है। उन्होंने चुनाव परिणामों में धांधली का आरोप भी लगाया है। बसपा प्रमुख ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में बसपा ने भी इस बार 19 सीटों पर अपने पार्षद जिताकर भेजे हैं। काफी उम्मीदवार सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी की वजह से दोबारा गिनती में जबरदस्ती थोड़े-थोड़े वोटों के अन्तर्ग से हरा दिये गये हैं, वरना पार्टी का बहा और भी अच्छे रिजल्ट आ सकता था। इसके लिए पार्टी का पहलू से अच्छे तरीका आवा है और वे भी बधाई के पात्र हैं। उम्मीद है कि अब वहां आगे होने वाले विधानसभा आमचुनाव में व देश में लोकसभा आमचुनाव में भी वे सभी

लोग अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लायेंगे। मायावती ने ओडिशा प्रदेश का खासकर पश्चिम और दक्षिण ओडिशा क्षेत्र के गणपद हनुआ खाड़ तिसार' के अवसर पर कहा कि मैं सभी जनसामान्य का प्रकृति से सुख, समृद्धि कामना करने के साथ-साथ सभी को नूआ जुहार करती हूं।

सुना है क्या: "विपक्षी गठबंधन से डील पक्की", "ट्रांसफर में करीबियों की मौज" और "जेन जी का खौफ"

एजेंसी लखनऊ। चुनाव के नजदीक आते जाते से हालात लगातार बदल रहे हैं तो नेता और अफसर अपने-अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। वहीं, जेन जी का खौफ भी सत्ता के सिर चढ़कर बोले रहा है क्योंकि सभी महकमे जानते हैं कि सख्ती की तो लेने के देने पड़ जायेंगे। देखें आज की कानफूसी: विपक्षी गठबंधन से डील पक्की सत्ताधारी दल से जुड़े एक पूर्व सांसद लहेलखंड की एक विधानसभा सीट से अपनी बेटी को लड़ाना चाहते हैं। यह सीट अभी सत्ताधारी दल के ही पास है और उसके एक अन्य नेता वहां से विधायक हैं। पूर्व सांसद को इस सीट पर एकाएक सक्रियता बढ़ी तो



दल के दूसरे नेता भी चौकन्ने हो गए। वहीं, पूर्व सांसद का दावा है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें इसी सीट पर तैयारी करने के लिए कह दिया है।

पक्की बात हो गई है... आगे आप खुद ही समझदार हैं। ट्रांसफर और चुनावी सीजन में इन दिनों 'बड़ों' के करीबियों की मौज है। खास तौर पर मलाईदार महकमों में बैठे बड़े साहबों के खासमखास मलाई काटने में बिज्जी हैं। ऐसे ही चार 'बढ़िया' महकमों में काबिज गैरकराहों के निकटतम फाइलों को निपटाने में दिन-रात पसीना बहा रहे हैं। उनके विभाग के अन्य लोग केवल बिल्ली के भाग्य से छीका फूटने का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ मलाई उनके हिस्से आ जाए। चर्चा जोरों पर है कि करीबी अपने साहबों को बताते कुछ हैं और 'लाते' कुछ हैं। यानी उन्हें मौका देने वालों की ही जेब काटने का मौका नहीं छोड़ रहे।

जेन जी का खौफ पश्चिम के एक कमिश्नरेट में जेन-जी पर सख्ती को लेकर मचा बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि राजधानी में इसकी चिंगारी थड़कने के हालात बन गए। अफसरों ने मौके की नजकत को धांपकर मान-मनौवल कर मामला सुला दिया, वरना लेने के देने पड़ सकते थे। खासकर स्टार वालों को यह समझने में देर लग रही है कि वे कोई विपक्ष का प्रदर्शन नहीं हैं। यहां सख्ती की तो उनके साथ तलवार वाले भी नभ जायेंगे। वैसे भी सोशल मीडिया के जमाने में सब सार्वजनिक हो जाता है। फिर देते रहिए सफाई और काटते रहिए बड़े अफसरों और अदालतों के चक्कर।

संपादकीय

पुस्तकें बिकती हैं, पाठकीयता नहीं

किताब छपी जा सकती है, प्रदर्शित की जा सकती है, उसका विज्ञापन किया जा सकता है, उस पर छूट दी जा सकती है और उसे बेचा जा सकता है। लेकिन पाठकीय संस्कृति केवल लिपिपणन के माध्यम से पैदा नहीं की जा सकती। कोई पुस्तक पाठक की अलमारी तक तो पहुँच सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह उसके मन और विचारों तक भी पहुँचे। किसी पुस्तक की वास्तविक सफलता केवल उसकी बिक्री के आंकड़ों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोगों ने उसे पढ़ा, उसके विचारों पर चिंतन किया और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया।

आज का प्रकाशन उद्योग अत्यंत प्रतिस्पर्धी हो गया है। प्रकाशक, लेखक और पुस्तक विक्रेता स्वाभाविक रूप से बिक्री, लोकप्रियता, रैंकिंग और व्यावसायिक सफलता पर ध्यान देते हैं। आकर्षक आवरण, प्रचार अभियान, सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने पुस्तकों को पहले की तुलना में अधिक मुलमल बना दिया है। फिर भी एक विरोधाभासी स्थिति सामने आ रही है—पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ रही है, लेकिन निरंतर और गंभीर पढ़ने की आदत कई चुनौतियों का सामना कर रही है। स्मार्टफोन और छोटे डिजिटल कंटेंट के बढ़ते प्रभाव ने लोगों के सूचना ग्रहण करने के तरीके को बदल दिया है। अनेक युवा वीडियो, सुविधों और छोटी-छोटी पोस्ट को तेजी से देखने और आगे बढ़ जाने के अभ्यस्त हो रहे हैं। किसी लंबे अध्यय को पढ़ने के लिए धैर्य, एकाग्रता और मानसिक सहभागिता की आवश्यकता होती है। छोटी डिजिटल क्लिप के विपरीत पुस्तक हमेशा तत्काल मनोरंजन या उत्तेजना प्रदान नहीं करती। वह पाठक से समय और ध्यान मांगती है।

यहीं पुस्तक बेचने और पाठक बनाने के बीच का अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को सिफारिश, बेस्टसेलर के लेबल या आकर्षक विज्ञापन से प्रभावित होकर खरीद सकता है। लेकिन खरीदना केवल शुरुआत है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब पाठक पुस्तक खोलता है, उसके विचारों से जुड़ता है, उन पर विचार करता है और अगली पुस्तक पढ़ने की इच्छा विकसित करता है। एक सच्ची पाठकीय संस्कृति धीरे-धीरे विकसित होती है—जिज्ञासा, पारिवारिक वातावरण, पुस्तकालयों, विद्यालयों और पुस्तकों पर सार्थक बातचीत के माध्यम से। इस प्रक्रिया में विद्यालयों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पढ़ने को केवल परीक्षा की आवश्यकता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर कहानियाँ, जीवनियाँ, विज्ञान की पुस्तकें, इतिहास, यात्रा-वृत्तांत, कविता और उनकी आयु के अनुरूप साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जब पढ़ना केवल परीक्षा से जुड़ा जाता है, तो वह बोझ जैसा लग सकता है। लेकिन जब पढ़ना खोज, आनंद और जिज्ञासा से जुड़ता है, तो यह जीवनभर की आदत बन सकता है।

परिवार भी बच्चों के पुस्तक-प्रेम को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस बच्चे के माता-पिता को पढ़ते हुए देखकर वह बड़ा होता है, उसके लिए पुस्तक केवल पढ़ाई का साधन नहीं रहती, बल्कि ज्ञान, कल्पना और मानसिक समीति का स्रोत बन जाती है। परिवार में प्रतिदिन कुछ मिनट साथ बैठकर पढ़ना भी बच्चों के मन में पुस्तकों के प्रति सकारात्मक भावना पैदा कर सकता है।

पुस्तकालयों को भी समय के साथ बदलना होगा। आधुनिक पुस्तकालय का काम केवल पुस्तकों को संग्रहित करना नहीं, बल्कि पाठक तैयार करना होना चाहिए। पठन क्लब, लेखक से संवाद, कहानी सुनाने के कार्यक्रम, पुस्तक परिचर्चाएँ और विद्यार्थियों द्वारा पुस्तक-सिफारिश जैसी गतिविधियाँ पुस्तकालयों की जीवंत सामुदायिक केंद्र बना सकती हैं। डिजिटल संसाधन मुद्रित पुस्तकों के विकल्प के बजाय उनके सहयोगी बन सकते हैं।

इसलिए चुनौती केवल अधिक पुस्तकें बेचने की नहीं है। चुनौती ऐसा वातावरण बनाने की है, जिसमें लोग स्वेच्छ से पढ़ना चाहें। प्रकाशक पुस्तकें बाजार तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन उन्हें लिख सकते हैं, शिक्षक उनकी सिफारिश कर सकते हैं और पुस्तकालय उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय पाठक का हो होता है। कोई विज्ञापन किसी व्यक्ति को जिज्ञासु बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कोई छूट एकाग्रता को गारंटी नहीं दे सकती।

माता-पिता वृद्धाश्रम में, बच्चे विदेश में, क्या यही है आधुनिक सफलता की कीमत?

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनार्नी

वैश्विक स्तर पर किसी भी सभ्य समाज की असली पहचान उसकी ऊँची इमारतों, चमकती सड़कों या आर्थिक समृद्धि से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों, कमजोरों और निर्भर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आज दुनियाँ तेजी से बदल रही है, बहुरंग परिवारों की जगह एकल परिवार ले रहे हैं, बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए महानगरो तथा विदेशों में बस रहे हैं और जीवन की भाग्यदी में कहीं माता-पिता की वह भावनात्मक जगह सिक्कड़ती जा रही है, जो कभी परिवार की नींव हुआ करती थी। सबसे पीड़ादायक स्थिति तब सामने आती है, जब जिन माता-पिता ने अपनी संतान की शिक्षा, करियर और भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, वही समय उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनसे दूरी बना लेती है। वृद्धाश्रमों की बढ़ती आवश्यकता माता-पिता को अकेला छोड़ देने की घटनाएँ और बुजुर्गों के साथ असमानवीय व्यवहार से जुड़े खतरनाक खंडितों केवल व्यक्तिगत त्रासदियाँ नहीं हैं; वे समाज की बदलती संवेदनशीलता पर गंभीर प्रतीक हैं। क्या आधुनिकता की कीमत अपनी जड़ों को भूल जाना है? क्या आर्थिक सफलता का अर्थ उस हाथ को भूल जाना है, जिन्हने हमें चलना सिखाया था? इसी व्यापक समाजिक और वैश्वीय चिंता के बीच 7 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में बुजुर्गों के अधिकारों से जुड़ी वर्ष 2016 से लंबित जनहित याचिका पर हुई सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण बन गई है। अदालत ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से वृद्धाश्रमों तथा वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

साथियों! बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट की दस्तक: क्या देश अपने बुजुर्गों के लिए सचमुच तैयार है? इसकी समझने की करें तो, 7 सितंबर 2026 की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जितेंद्रगाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे, ने लंबे समय से लंबित इस मामले को फिर गंभीरता से उठाया। वर्ष 2016 में पुरुष केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका का मूल प्रश्न केवल वृद्धाश्रमों की संख्या तक सीमित नहीं है; यह उस व्यापक अधिकार से जुड़ा है जिसके तहत प्रत्येक बुजुर्ग को सम्मान, सुरक्षा, आश्रय, स्वास्थ्य सुविधा और गरिमापूर्ण जीवन मिलना चाहिए। अदालत ने अर्दनों जनरल को निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एडवोकेट जनरल तथा स्टैंडिंग काउंसिल से संपर्क कर वृद्धाश्रमों की स्थाना और वहां उपलब्ध सुविधाओं की ताजा जानकारी जुटाई जाए। राज्यों को संबंधित पत्र मिलने के बाद लगभग चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। यह निर्देश महज प्रशासनिक औपचारिकता नहीं माना जाना चाहिए। इसके पीछे एक बुनियादी सवाल है, कागजों पर बुजुर्गों के लिए कितनी योजनाएँ हैं और जमीन पर वास्तव में उन्हें सटीकता से कितना सहारा मिल रहा है?

साथियों, बात अगर हम अनुच्छेद 21 बुजुर्गों के लिए सिर्फ जीवन नहीं, गरिमा का जीवन को समझने की करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। बुजुर्गों के संदर्भ में यह सवाल और भी व्यापक हो जाता है, क्या केवल सांस लेते रहना ही जीवन है, या जीवन का अर्थ सम्मान, सुरक्षा स्वास्थ्य, आश्रय और गरिमा के साथ जीना भी है?

वर्ष 2016 की इस जनहित याचिका में इसी व्यापक दृष्टिकोण से बुजुर्गों के लिए आश्रय, पर्याप्त पेंशन, जैरिव्याटिक चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग उठाई गई है।

भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है ब्रिक्स का साझा प्रस्ताव

अशोक मधुप

बहुभूवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण और विकासशील देशों की एकजुटता के इतिहास में एक अत्यंत मौल का पथर सिद्ध हुआ है। इस सम्मेलन ने न केवल ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के आर्थिक एवं राजनीतिक महत्व को रेखांकित किया, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दिया कि वैश्विक शासन व्यवस्था में अब हग्लोबल साउथह की आवाज को लंबे समय तक अनसुना नहीं किया जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित पश्चिमी प्रभुत्व वाली वित्तीय और कूटनीतिक प्रणालियों, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की एकाधिकारवादी नीतियों के उतर में दिल्ली सम्मेलन एक सशक्त प्रतिमान बनकर उभरा। भारत की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स (बीरिक्स) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच मतभेदों के बावजूद भारत ने एक साझा हस्तसम्मतिह बनाने में सफलता हासिल की। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता है कि तमाम भू-राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भारत सभी सदस्य देशों की 45 से अधिक पेजों वाले सर्वसम्मति हानई दिल्ली घोषणापत्रह पर सहमत करने में सफल रहा। इसमें आतंकवाद के सभी रूपों की कड़े शब्दों में निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ हजरो रॉटरसह तथा उसकी फॉरिग रोकेने का साझा संकल्प लिया गया। इससे पहले के सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र जारी कराना एक कठिन काम था।

ब्रिक्स के सदस्य देशों के अपने-अपने राणनीतिक हित, क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ और विदेश नीति संबंधी विचार हैं। पश्चिम एशिया के



मसले पर यह विविधता और भी साफ दिखाई देती है। ईरान स्वयं संघर्ष में एक प्रमुख पक्ष है। उसके सऊदी अरब और यूएई के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर मतभेद हैं। साझा बयान में न तो अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों का और न ही इसके बाद ईरान द्वारा फारस की खाड़ी के अपने पड़ोसी देशों पर किए गए हमलों का सीधे तौर पर जिक्र किया गया। इसमें युद्ध के दौरान ह्यअधिकतम संयमह बरतने की अपील की गई। इस साझा बयान में भारत ने यह दिशाया कि कठिन भू-राजनीतिक परिस्थितियों में असहमतियों को अलग रखकर भी संवाद के रास्ते खुले रखे जा सकते हैं। वे साझा घोषणापत्र बुद्ध खत्म नहीं करा फिर भी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में सहमति की दिशा में उठा हर कदम महत्व रखता है। प्रस्ताव में सदस्य देशों के बीच व्यापार में आने वाली शीर्ष 10 बड़ी सकावटों की चिन्हित कर हटाने का लक्ष्य रखा गया। हर साल 100 नए

अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप का एक-दूसरे के बाजारों में विस्तार और कंपनियों के बीच 1,000 नई साझेदारियों बनाने की योजना और शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने और जलवायु-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने पर सहमति बनी। वैश्विक आधुनि श्रृंखलाओं और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिकी डॉलर पर अल्पधिक निर्भरता घटाने, स्थानीय मुद्राओं में सीमा-पार भुगतान को बढ़ावा देने तथा हान्यू डेवलपमेंट बैंकह के विस्तार पर प्रगति हुई। इस सम्मेलन में भारत के सफल ह्यडिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरह (नूपीआई, आधार मांडल आदि) को ब्रिक्स देशों के साथ साझा करने पर मुहर लगी। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को सुरक्षित, पारदर्शी और ग्लोबल साउथ के हितों के अनुकूल बनाने के लिए साझा मानक तय करने पर बल दिया गया।

सम्मेलन के द्तर भारत की बड़ी उपलब्धि है वैश्विक नेताओं के

साथ महत्वपूर्ण बातचीत। लंबे समय से चल रहे सीमा तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सीधी बातचीत हुई। इसमें मतभेदों को विवाद में न बदलने और सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले बड़ा कदम छह साल बाद भारत-चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करना है। भारत-रूस के बीच ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर सहमति जताई गई।

सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में तत्काल सुधार की मांग को मजबूती से दोहराया गया, ताकि विकासशील देशों को वैश्विक निर्माण लेने की प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। भारत ने इस सम्मेलन के जरिए यह साबित किया कि वह वैश्विक मुद्दाजी से दूर रहकर एक संतुलित और निष्पक्ष ह्यआर्थिक और कूटनीतिक

पुलह के रूप में काम करने की क्षमता रखता है।

दिल्ली शिखर सम्मेलन ने यह साबित किया कि ब्रिक्स अब केवल एक विचार-विमर्श का मंच या बयानों तक सीमित रहने वाला समूह नहीं रहा, बल्कि यह संस्थागत ढांचा तैयार करने में सक्षम एक ठोस आर्थिक ब्लॉक बन चुका है। इसके अतिरिक्त, देशों के वित्तीय संकट से निपटने के लिए आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था पर चर्चा ने सदस्य राष्ट्रों को वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव से एक सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास किया।

व्यापारिक दृष्टिकोण से दिल्ली सम्मेलन में एक अत्यंत दूरदर्शी निर्णय यह लिया गया कि सदस्य देश आपस में अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देंगे। अंतर-ब्रिक्स व्यापार में अमेरिकी डॉलर और यूरो पर निर्भरता कम करने के इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य क्रेडिट सुविधाओं को आसान बनाना और विनिमय दरों के जोखिमों को कम करना था। पश्चिमी वित्तीय आधिपत्य और प्रतिबंधों की राजनीति के आलोक में यह फल वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी गई।

इसके साथ ही, व्यापार मंत्रियों के स्तर पर हुए समझौतों ने यह सुनिश्चित किया कि सदस्य देशों के बीच माल, सेवाओं और निवेश का प्रवाह सुचारु रूप से हो सके। यदि दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन का विक्षेपण किया जाए, तो इसके बहुआयामी सकारात्मक परिणामों के साथ-साथ कई ऐसे अंतर्विरोध और सीमाएँ भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं जो इस समझौते की दक्षता को चुनौती देती हैं। सबसे बड़ा

अंतर्विरोध ब्रिक्स के दो सबसे बड़े सदस्यों—भारत और चीन—के बीच मौजूद रणनीतिक और सीमा संबंधी अविश्वास है। दिल्ली सम्मेलन के मंच पर जहां दोनों देशों के नेतृत्व ने आर्थिक सहयोग पर सकारात्मक प्रतिबद्धता दिखाई, वहीं परदे के पीछे सीमा विवाद, क्षेत्रीय आधिपत्य की होड़ और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का आक्रामक रुख एक अन्सुलझी चुनौती बना रहा। शासन प्रणालियों और विचारधाराओं का अंतर भी इस सम्मेलन की एक बड़ी सीमा के रूप में रेखांकित हुआ। भारत और ब्राजील जहां जीवंत लोकतांत्रिक देश हैं, वहीं चीन और रूस में एकदलीय अथवा सत्तावादी शासन संरचनाएँ हैं। इस वैचारिक भिन्नता के कारण अंतरराष्ट्रीय कानूनों, मानवाधिकारों और वैश्विक नीतियों पर ब्रिक्स का एक एकीकृत दृष्टिकोण बना पाना बेहद जटिल हो जाता है। पश्चिमी देश किसी भू-राजनीतिक संकट पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो रूस और चीन का रुख स्पष्ट रूप से पश्चिम-विरोधी होता है, जबकि भारत और ब्राजील एक हगरी-पश्चिमीह लेकिन ह्यपश्चिम-विरोधी नहींह का संतुलन पसंद करते हैं। दिल्ली सम्मेलन में भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने इस सम्मेलन को किसी सीधे पश्चिम-विरोधी मोर्चे में तब्दील होने से रोक और इसे विकास केंद्रित बनाए रखा।

जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी दिल्ली सम्मेलन में व्यापक मंथन हुआ। सम्मेलन ने यह स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन के पेंतिहासिक उत्तरदायित्व के लिए विकसित देशों को घन और तकनीक हस्तांतरण की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

बसपा में उथल-पुथल, आकाश आनंद और दलित वोटरों पर सबकी नजर

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की सिंयासत में इन दिनों बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के भीतर मचे घमासान से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आशिष पार्टी का परंपरागत दलित वोट बैंक अब किस दिशा में जाएगा। मायावती ने 3 सितंबर 2026 को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटाया था, और महज एक हफ्ते बाद 10 सितंबर को उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी पूरी तरह मुक्त कर दिया। आकाश के समुर अशोक सिद्धार्थ ने भी इसी दौरान सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी, जिससे बसपा के भीतर पारिवारिक विवाद खुलकर सामने आ गया। हाल ही में लखनऊ में मीडिया से बातचीत में मायावती ने अपनी संकेत को लेकर उड़ी अचवाहों और आकाश आनंद के एक फोन कॉल का जिक्र करते हुए कड़ी नाराजगी भी जताई। इस पुरे प्रकरण ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा की संगठनात्मक स्थिति को कमजोर कर दिया है, और यहीं कमजोरी अब दूसरे दलों के लिए मौका बन गई है। मायावती के फैसले के फौरन बाद नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (काशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आनंद ने आकाश आनंद के लिए अपनी पार्टी का दरवाजा खोल दिया। चंद्रशेखर ने आकाश को छोटा भाई बताते हुए कहा कि दोनों



मिलकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय राज्यमंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के प्रमुख रामदास आठवले ने भी यही कोशिश दोहराई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यूपी में बसपा से अनाह हक वापस लेने का आह्वान किया और बाद लिलाया कि सत्तर के दशक में जो चुनाव विड आरपीआई के पास था, वही अब बसपा इलेमाल कर रही है। आठवले ने साफ कहा कि अगर आकाश आनंद बसपा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें आरपीआई से जुड़ना चाहिए, इससे यूपी में संगठन मजबूत होगा।

इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी एक प्रकरार के सवाल पर कह चुके हैं कि अगर कोई प्रकरार आकाश आनंद को उनके पास लेकर आए तो वे उन्हें सपा में शामिल कर लेंगे।

इन तीनों दलों की दिलचस्पी में एक साझा गणित छिपा है। आकाश

आनंद भले ही संगठनात्मक तौर पर अभी अनुभवहीन माने जाते रहे हों, लेकिन बसपा के युवा और शहरी दलित समर्थकों में, खासकर सोशल मीडिया पर, उनको एकड़ काफी मजबूत रही है। मायावती लंबे समय से खुद को बाबा साहेब के मिशन और काशीराम की विरासत का इकलौता वाहक बताती रही हैं, और आकाश को उन्होंने ही इस विरासत का अगला चेहरा बनाकर पेश किया था। ऐसे में अगर आकाश किसी और दल से जुड़ते हैं तो वे उस दल की बसपा की वैचारिक विरासत और उसके जनाधार, दोनों से जोड़ने वाली एक कड़ी बन सकते हैं। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद और रामदास आठवले जैसे नेता, जो खुद अंबेडकरवादी राजनीति की जमीन पर खड़े हैं, आकाश को अपने पाले में लाकर बसपा के कमजोर पड़ते जनाधार का सीधा फायदा उठाना चाहते हैं। बसपा का दलित वोट बैंक, खासकर जाटव समुदाय के बीच, उत्तर प्रदेश की सिंयासत में दशकों से एक निर्णायक ताकत रहा है।

यह वोट बैंक भले ही पिछले कुछ चुनावों में सिक्कड़ता दिखा हो, फिर भी यह इतना बड़ा जरूर है कि जिस भी गठबंधन या दल के साथ यह जुड़ जाए, चुनावी नतीजों की दिशा बदल सकता है। मौजूदा उथल-पुथल के बीच कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि मायावती खुद अपनी पार्टी को कमजोर करने पर तुली हैं, जबकि सपा प्रवक्ताओं की ओर से भी बसपा पर परोक्ष रूप से भाजपा की नीतियों का साथ देने के आरोप लगाए गए हैं। यानी विपक्षी खेमे के लगभग सभी बड़े दल इस मौके को बसपा के परंपरागत मतदाताओं में सेंध लगाने के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल हर दल की रणनीति अलग है। चंद्रशेखर आजाद खुद दलित राजनीति की जमीन पर खड़े हैं और सीधे तौर पर बसपा के वोट बैंक के प्रतिद्वंदी दावेदार हैं। इसलिए उनके लिए आकाश आनंद जैसा चेहरा मिलना वैचारिक तालमेल के साथ-साथ संगठनात्मक विस्तार का भी मौका है। रामदास आठवले और आरपीआई के लिए यह मौका उत्तर प्रदेश में लगभग खत्म हो चुकी अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से खड़ा करने का है, भले ही आरपीआई फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। वहीं सपा और कांग्रेस के लिए यह मौका अपने मौजूदा सामाजिक समीकरण, यानी पिछड़ा-मुस्लिम या सामान्य-दलित गठजोड़ में दलित वोटों की और ज्यादा हिस्सेदारी जोड़ने का है।

डॉ. प्रियंका सौरभ

हम अपने घर को साफ रखने के महत्व से अवगत हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमारी जिम्मेदारी की भावना गायब हो जाती है। कई लोगों की घरेलू सामान सफाई के किनारे, नाले में, खाली जगह पर या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने की आदत पड़ गई है। प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन, सचिन्यों के छिलके, फलों के अवशेष और बचा हुआ खाना नियमित रूप से खुले में फेंक दिया जाता है। लेकिन लापरवाही का यह मामूली सा काम धीरे-धीरे लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। खुले में कूड़ा फेंकने से वह सड़ने लगता है और दुर्गंध आने लगती है। समस्या केवल ह्यअसुविधाह की नहीं है। कचरे के जमाव से गंदगी फैलती है और मक्खियों, मच्छर, आबावा जानवर और अन्य कोट आकर्षित होते हैं। प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ नालियों को जाम कर सकते हैं जिससे बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है। पानी के बहाव में कमी से सचिन्यों के पनपने के स्थान बन जाते हैं और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यदि कोई एक व्यक्ति लापरवाही बरतता रहता है, तो यह पूरे मोहल्ले के लिए स्वास्थ्य समस्या बन सकता है।

सबसे बुरी बात यह है कि समाज के लोग इसे एक सामान्य बात समझने लगे हैं। हम सड़क किनारे कचरे के ढेर देखते हैं, कूड़ा पत के लिए नाक ढक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।

शांति, स्वतंत्रता और समानता का बुनियादी स्तंभ है लोकतंत्र

ललित गर्ग

लोकतंत्र केवल मतपत्र पर लगाई गई मुहर का नाम नहीं है। यह उस विश्वास का नाम है जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज, अपनी गरिमा और अपने अधिकारों के साथ राष्ट्र-निर्माण में सहभागी होने का अवसर मिलता है। एक तरह से शांति, स्वतंत्रता, समानता एवं सह-जीवन का बुनियादी स्तंभ है लोकतंत्र। हर वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इसी लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करने का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में इस दिवस की स्थापना की थी और 2008 से इसका आयोजन हो रहा है। 2026 में अंतर-संसदीय संघ-आईपीयू ने लोकतंत्र दिवस के लिए ह्यमानवाधिकारों को केंद्र में लाएह को प्रमुख विषय बनाया है। इसका संदेश स्पष्ट है कि मानवाधिकार लोकतंत्र के सजावटी तत्व नहीं, बल्कि उसकी बुनियादी शर्त हैं। मानवाधिकार सुरक्षित नहीं हैं तो चुनाव, संसद और संविधान की मौजूदगी के बावजूद लोकतंत्र अधूरा रहेगा।



आज दुनिया के सामने लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या लोकतंत्र केवल संस्थागत ढांचे के रूप में जीवित है या उसके भीतर नागरिक स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संवाद और मानवीय गरिमा भी सुरक्षित हैं? संयुक्त राष्ट्र की 2026 में लोकतंत्र को केवल चुनावों तक सीमित न मानते हुए मानवाधिकार, कानून के शासन और नागरिकों की सार्थक भागीदारी को

उसकी अनिवार्य आत्मा मान रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। लेकिन इसकी कमजोरी यी यहीं से शुरू होती है। जब जनता अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है, जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं लेकिन कर्तव्यों के प्रति मानते हुए मानवाधिकार, कानून के शासन और नागरिकों की सार्थक भागीदारी को

उसकी अनिवार्य आत्मा मान रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। लेकिन इसकी कमजोरी यी यहीं से शुरू होती है। जब जनता अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है, जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं लेकिन कर्तव्यों के प्रति मानते हुए मानवाधिकार, कानून के शासन और नागरिकों की सार्थक भागीदारी को

के प्रभाव में आने लगते हैं, तब लोकतंत्र का बाहरी ढांचा तो बचा रहता है, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है। आज दुनिया के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियाँ हैं। राजनीतिक धूवीकरण बढ़ रहा है। संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर दबाव दिखाई देता है। तथा सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कई समाजों में चिंता का कारण बन रही है।

लोकतंत्र के नाम पर चुनाव हो जाना पर्याप्त नहीं है। यदि चुनाव के बाद नागरिकों की आवाज को महत्व न मिले, विपक्ष को शत्रु समझा जाए, मीडिया स्वतंत्र न रहे, न्यायपालिका पर दबाव हो और सत्ता जवाबदेही से मुक्त होने लगे, तो लोकतंत्र धीरे-धीरे बहुमत की निरंकुशता में बदल सकता है। महात्मा गांधी का लोकतंत्र संबंधी चिंतन आज भी इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था— हमारे विचार में लोकतंत्र में सबसे कमजोर व्यक्ति को वही अवसर मिलना चाहिए जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मिलता है। गांधी जी के

लिए लोकतंत्र केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं था, बल्कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था था। वे लोकतंत्र को अहिंसा, अनुशासन, लास्यम और नागरिक चेतना से जोड़ते थे। उनका स्पष्ट विचार था कि लोकतंत्र हिंसा और असत्य के सहारे कायम नहीं रह सकता। विंस्टन चर्चिल का प्रसिद्ध कथन भी लोकतंत्र की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करता है। लोकतंत्र शासन की सबसे खराब प्रणाली है, उन सभी प्रणालियों को छोड़कर जिनमें आजमाया जा सकता है। यह कथन लोकतंत्र की कमियों को स्वीकार करते हुए भी उसकी श्रेष्ठता को रेखांकित करता है। लोकतंत्र पूर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसमें आत्म-सुधार की क्षमता है। जनता सरकार को चुन सकती है, उसकी अज्ञानता सन्न कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदल सकती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है— सत्ता का शक्तिपूर्ण हस्तांतरण। जहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा, क्रांति या रक्तपात की आवश्यकता नहीं पड़ती।

संक्षिप्त

समाचार

एक देश, दो हिस्से और तीन दशक की हिंसा- ट्रंप ने फिर क्यों उठाया आयरलैंड को एक करने का मुद्दा विवाद की कहानी

दूनबेग, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे मुद्दे पर खुलकर राय रख दी, जिस पर ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच लंबे समय से गहरी राजनीतिक और भावनात्मक खाई रही है। ट्रंप ने कहा कि वह आयरलैंड को एक होते देखना चाहते हैं। रविवार को आयरलैंड के डूनबेग में अपने गोलफ कोर्स पर आयरिश ओपन के दौरान उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड को एक साथ कर देना दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीजों में से एक है। एक दिन पहले उन्होंने एकीकृत आयरलैंड को 'शानदार' बताया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनके लिए यह कोई असामान्य बात नहीं है कि आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड एक हो जाएं। हालांकि उन्होंने रविवार को यही कहा कि यह केवल उनकी राय है और उन्हें इस विचार के लिए काफी समर्थन मिला है। समस्या यह है कि उत्तरी आयरलैंड का ब्रिटेन में रहना या आयरलैंड के साथ जुड़ना केवल दो इलाकों को मिलाने का मामला नहीं है। इसके पीछे करीब एक सदी का इतिहास, दो अलग समुदायों की पहचान और कई दशकों की हिंसा जुड़ी हुई है।

चीन में शहर-शहर बारिश का कहर: हैनान प्रांत से 31 हजार से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू; अभी कैसे हैं हालात

बीजिंग, एजेंसी। चीन के हैनान प्रांत में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जोरिम वाले इलाकों से 31 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रांतीय आपदा रोकथाम और राहत समिति के मुताबिक, रविवार शाम 7:50 बजे तक कुल 31,564 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हालांकि, अब तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। शुक्रवार सुबह आठ बजे से रविवार शाम चार बजे तक हैनान के छह शहरों और जिलों के 24 टाउनशिप में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इनमें वानिंग, लिंगशुई और वयोंगहाई भी शामिल हैं। वानिंग के चांगफंग टाउनशिप में सबसे ज्यादा 452.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने रविवार शाम से सोमवार तक और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। भारी बारिश और बाढ़ के खतरों को देखते हुए हैनान ने रविवार सुबह 11 बजे बाढ़ नियंत्रण के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया को बहाक लेवल-2 कर दिया। इसके बाद रविवार शाम 7 बजे वानिंग ने लेवल-1 आपातकालीन प्रतिक्रिया लागू कर दी।

सिंगापुर में भारतवर्षी सीईओ की याचिका खारिज, पूर्व प्रेमिका से वसूलने थे 3.5 करोड़ रुपये

सिंगापुर, एजेंसी। सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक सीईओ को अपनी पूर्व प्रेमिका पर खर्च किए गए करीब 3.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूलने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, अधिकांश राशि उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को उधार के तौर पर दी थी। मुंबई में सूचीबद्ध एक कंपनी के सीईओ वंदर अग्रवाल ने अपनी पूर्व प्रेमिका पर मुकदमा दायर कर उसके ऊपर खर्च की गई विभिन्न रकम वापस मांगी थी। अग्रवाल का दावा था कि यह राशि ऋण के तौर पर दी गई थी और उसे वापस किया जाना था। इन खर्चों में विदेश यात्राओं, उसके प्लैट के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सेवाएं और स्टैफोर्ड-एनयूएस के कार्याकारी कार्यक्रम की फीस शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दोनों की मुलाकात 2019 में एक उड़ान के दौरान हुई थी। इसके बाद अग्रवाल ने सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क किया।

2028 के चुनाव को लेकर ट्रंप ने क्या बयान दिया

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल लगातार चर्चा में है। कभी उनकी टीम के अधिकारियों के इस्तीफे पर चर्चा होती है तो कभी देश की राजनीति में नंबर दो माने जाने वाले उपराष्ट्रपति को लेकर अटकलें लगती हैं। ताजा घटनाक्रम में ट्रंप ने 2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मौजूदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का समर्थन करने से जुड़े सवाल को लेकर कहा, अभी बहुत जल्दी है। वह बहुत बढ़िया शख्स हैं... हमारे पास बहुत सारे अच्छे विकल्प हैं... वे सभी बहुत अच्छे हैं।' भारतवर्षी महिला उपा से शादी करने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में थोड़े नरम तेवरों के लिए जाने जाते हैं। इसकी मिसाल उस समय दिखी थी, जब प्रियम पटिया में तनाव के बीच ईरान ने ट्रंप के दामाद कुमरान और एक अन्य वार्ताकार विटक्रॉफ की जगह बातचीत के लिए वेंस को पहली पसंद बताया था।

ईरान के तेल पर अमेरिका की नजर ट्रंप बोले- जरूरत पड़ी तो लागू करेंगे वेनेजुएला मॉडल

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संकेत दिया कि युद्ध खत्म होने के बाद भी अमेरिका ईरान के आस-पास अपनी मौजूदगी बनाए रख सकता है और उसके तेल संसाधनों पर नियंत्रण कर सकता है। ट्रंप ने इसकी तुलना वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के सत्ता से हटाए जाने के बाद अमेरिका की भूमिका से की। आयरलैंड दौरे के दौरान आयरिश ओपन गोलफ चैंपियनशिप में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अंततः ईरान से बहर निकल जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह वहां रुककर 'वेनेजुएला की तरह तेल अपने पास रख सकता है।' हालांकि ट्रंप के इस बयान पर अब तक ईरान ने किसी भी तरह का पलटवार नहीं किया है।

मध्यावधि चुनाव के बाद खत्म हो सकता है युद्ध : ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के साथ युद्ध

ए-380 की विदाई शुरू: कभी आसमान का ‘बादशाह’ था सुपरजंबो, अब क्यों सिमट रहा इसका सफर



रिकवरी और नए विमानों की डिलीवरी में देरी ने ए-380 को एक और मौका दे दिया। एयरबस और बोइंग के नए विमानों की उत्पादन संबंधी समस्याओं, खासकर बोइंग 777एक्स की लंबी देरी के बीच कई एयरलाइंस ने अपने ए-380 फिर से उड़ाने शुरू कर दिए।

दो मॉजिलों वाला विमान, जो खुद में एक अनुभव था : ए-380 की सबसे बड़ी खासियत उसका आकार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान है और इसकी पूरी लंबाई में दो डेक यात्रियों के लिए इन्स्टोल किए जा सकते हैं। सामान्य कॉन्फिगरेशन में इसमें 500 से ज्यादा यात्री बैठ सकते हैं, जबकि अधिक घनी सीटिंग में क्षमता 800 से ज्यादा यात्रियों तक पहुंच सकती है।इसका विशाल आकार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। चौड़े केबिन और दो डेक की वजह से इसमें यात्रियों को दूसरे बड़े विमानों की तुलना में ज्यादा खुलापन महसूस होता है। उड़ान के दौरान इसकी स्थिरता और अपेक्षाकृत कम शोर भी यात्रियों को आकर्षित करता

लाभदायक बनाने के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों की जरूरत होती है।

आसमान में चलता-फिरता लगजरी अनुभव : ए-380 ने विमान यात्रा में लगजरी की नई तस्वीर भी बनाई। हालांकि इसकी सभी आलीशान सुविधाएं विमान की तकनीकी विशेषताएं नहीं थीं, एयरलाइंस ने इसके विशाल केबिन का इस्तेमाल अलग- अलग तरह से किया। एमिरेट्स ने अपने ए-380 में ऑनबोर्ड शॉवर और बार जैसी सुविधाओं को लोकप्रिय बनाया। एतिहाद ने इसी विमान में 'द रैंजर्डेस' जैसी बेहद महंगी निजी सुविधा पेश की, जिसमें निजी कमरा, बेडरूम और अलग रहने की जगह जैसी सुविधाएं थीं। सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने ए-380 के फर्स्ट क्लास में डबल-बेड वाले सुइट तक उपलब्ध कराए।यानी ए-380 सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला विमान नहीं था। यह एयरलाइंस के लिए ब्रांड, प्रतिष्ठ और लगजरी का प्रदर्शन भी बन गया था। समस्या यह है कि विमान कंपनियां अब सिर्फ प्रतिष्ठ नहीं, मुनाफा देखती हैं। ए-380 को भरपूर यात्रियों के साथ उड़ाना जरूरी है, जबकि नई पीढ़ी के छोटे विमान कम सीटों के साथ भी लंबी दूरी तय कर सकते हैं।नए टिवन-इनजन विमान अपेक्षाकृत कम ईंधन खर्च करते हैं। उन्हें ऐसे रूटों पर भी चलाया जा सकता है जहां ए-380 जैसी भारी क्षमता की जरूरत नहीं होती।

ईरान के बदले सुर: पीएम मोदी-जिनपिंग मुलाकात के बाद भरोसा बहाली की बात

बीजिंग, एजेंसी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और बिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद चीन के संकेत बताते हैं कि बीजिंग भारत के साथ संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य और स्थिर करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के विश्लेषण में सीमा पर तनाव नियंत्रित रहने, आर्थिक संपर्क बढ़ने और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को रिशतों को मजबूत करने के प्रमुख रास्तों के रूप में रेखांकित किया गया है। पेकिंग विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र के कार्यकारी उपनिदेशक वांग शूयू के मुताबिक राजनीतिक भरोसा केवल शीर्ष नेताओं की मुलाकात से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से बनता है। उन्होंने सीमा मुद्दे के प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र मजबूत करने, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने तथा व्यापार और निवेश को सुरक्षा के जरूरिये से देखने से बचने की जरूरत बताई। भारत और चीन के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा सीमा विवाद है। 2024 में कजान और 2025 में तियानजिन के बाद नई दिल्ली में मोदी-

जिनपिंग मुलाकात को चीन संबंधों में स्थिरता की अगली कड़ी के तौर पर देख सकते हैं। सीमा प्रबंधन में प्रगति, सीमा व्यापार और सीधी उड़ानों की बहाली को इसी प्रक्रिया के सकारात्मक संकेतों के रूप में पेश किया गया है।बीजिंग का जोर फिलहाल सीमा विवाद के तत्काल समाधान से ज्यादा उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर दिखाई देता है, ताकि सीमा का तनाव व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क को प्रभावित न करे। चीनी विशेषज्ञों के अनुसार संस्थागत मंचों पर मजबूत होने से ग्लोबलफरमी और अस्थिराश्त तनाव का जोरिम कम किया जा सकता है। इससे दोनों देशों के लिए दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की गुंजाइश बनेगी। आर्थिक रिशतों की गति देना चीन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में भारतीय थिंक टैंक ब्यूरो ऑफ रिसर्च ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ने भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में है और दोनों देशों के बीच सहयोग की काफ़ी संभावनाएं हैं।

राष्ट्रपति चुनाव 2028: जेडी वेंस के समर्थन पर ट्रंप का सस्पेंस बरकरार; बोले- कई बेहतरीन लोगों का विकल्प खुला



वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के समर्थन के सवाल पर फिलहाल कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि किसी उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए अभी काफी समय है। हालांकि, ट्रंप ने वेंस की जमकर तारीफ की और उन्हें शानदार बताया। आयरलैंड के शैनन में एयर फोर्स वन में सवार होने से पहले प्रेसकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप से पूछ गया कि क्या वह 2028 के चुनाव के लिए वेंस का समर्थन करने को तैयार हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा करना जल्दबाजी होगी। ट्रंप ने कहा कि उनके पास कई शानदार लोग हैं और पार्टी के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है।

ट्रंप ने वेंस की तारीफ की :

ट्रंप से जब पूछ गया कि वेंस के

समर्थन के संकेत दे चुके हैं ट्रंप इससे पहले अगस्त में द वाशिंगटन पोस्ट को एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस में दानदाताओं के साथ एक निजी बैठक के दौरान वेंस की संभावित उम्मीदवारी को लेकर अधिक स्पष्ट रुख दिखाया था। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने वहां कहा था कि अंततः जेडी वेंस को निर्वाचित कराना होगा।

हालांकि, उस समय ट्रंप के सलाहकारों ने संकेत दिया था कि राष्ट्रपति ने अभी अपने उत्तराधिकारी को लेकर अंतिम फैसला नहीं किया है। ट्रंप जेडी वेंस के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे थे। वेंस और रूबियो को लेकर पार्टी में चर्चा रिपोर्ट के मुताबिक, उस दौरान ट्रंप अपने सहयोगियों से वेंस और रूबियो की तुलना को लेकर लगातार सवाल करते रहे थे।

ईरान-ओमान वार्ता के बीच होर्मुज में जहाज पर हमला, खाड़ी देशों की बैठक टली; सामने आया बड़ा कारण



तेहरान/काहिरा, एजेंसी। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में प्रस्तावित बैठक को स्थगित कर दिया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया। हालांकि, ईरानी विदेश मंत्रालय के अधिकारों ने यह नहीं बताया कि किन देशों ने बैठक टालने का अनुरोध किया था।

ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-नुसैदी ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक स्थगित होने की जानकारी दी। यह बैठक ओमान के सलालाह शहर में होनी थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सहगति के हित में बैठक को टाला गया है और ओमान क्षेत्र में स्थिरता और लंबे समय तक सहयोग को बढ़ावा देने वाली बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग पर होनी थी चर्चा : बैठक का मुख्य एजेंडा होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को लेकर संभावित व्यवस्था पर चर्चा करना था। ईरान और ओमान पिछले कई महीनों से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से जहाजों के आवागमन के नियमों को लेकर द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं। ओमान जलडमरूमध्य के दूसरी ओर स्थित तट पर नियंत्रण रखता है और पहले यह कहा जा चुका है कि इन वार्ताओं को अन्य खाड़ी अरब

सोचने का तरीका गलत क्या वाकई एआई ताकतवर होता जा रहा है या फिर ईसान के दिमाग की बनावट और सोचने का तरीका इसकी वजह है। ईसान को अनजान और नई चीजों का ज्यादा डर हमारा दिमाग खतरों का अंदाजा आंकड़ों से नहीं, नियंत्रण के अहसास से लगाता है। लोग यह नहीं समझते कि एआई अंदर से कैसे काम करता है। नियंत्रण खोने के अहसास की वजह से लोगों में एआई का खोफ ज्यादा है। सड़क हादसों में रोज हजारों लोग मरते हैं, फिर भी हम कार चलाने से नहीं डरते। लेकिन हवाई जहाज के क्रैश होने का डर ज्यादा लगता है क्योंकि वहां हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता।

अदृश्य खतरे तो पहले से ही मौजूद : वैज्ञानिकों का कहना है, दुनिया खत्म होने के वास्तविक गणित में एआई का डर अभी काफी पीछे है। लैब से किसी खतरनाक वायरस का लोक होना या प्राकृतिक महामारी फैलना (3% संभावना) एआई के बेकाबू होने से कहीं अधिक बड़ा और तात्कालिक खतरा है। एआई से दुनिया खत्म होने के डर को टेक कंपनियों और कुछ लोगों की तरफ से बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जब लोग साइंस-फिक्शन फिल्मों की तरह एआई को एक खलनायक मान लेते हैं, तो एआई की असरदार और वास्तविक समस्याओं (जैसे साइबर फ्रॉड, डीपफेक और जासूसी और नौकरियों पर असर) से ध्यान भटक जाता है।

भारत ने PCB चीफ से फिर ट्रॉफी नहीं ली

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत ने विमेंस एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार खिताब जीता। हालांकि, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान फेर ने नकवी को 'चोर' कहकर भी चिढ़ाया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार ने गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत बिरोधी बयान दिए थे। इस वजह से 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने उनके हाथों एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली थी। अब भारतीय विमेंस टीम ने उखी स्टैंड पर कायम रहते हुए नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैच में स्मृति मंधाना और शोफाली चर्मा ने ट्रॉफी के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी की। टीम



इंडिया ने पूरे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 32 छक्के लगाए। पिछले साल भारतीय मेंस टीम ने भी नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी। तब सूर्यकुमार यादव ने खाली हाथ ही ऐसा जेस्चर बनाया, मानो वे ट्रॉफी लेकर आ रहे हों। 'ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला BCCI का' भारतीय महिला टीम के हंड कोच अमोल मन्गुदर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'ट्रॉफी नहीं लेने

नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी। तब सूर्यकुमार यादव ने खाली हाथ ही ऐसा जेस्चर बनाया, मानो वे ट्रॉफी लेकर आ रहे हों। 'ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला BCCI का' भारतीय महिला टीम के हंड कोच अमोल मन्गुदर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'ट्रॉफी नहीं लेने

BCCI ने दिए थे दो विकल्प

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारतीय टीम नकवी से ट्रॉफी लेने के पक्ष में नहीं थी। बोर्ड ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए दो विकल्प सुझाए थे।

का फैसला BCCI ने लिया है और हम फैसले के साथ हैं। हमारे लिए यह ट्रॉफी खतम हो चुका है। हम चैंपियन हैं। हमारे लिए इतना ही काफी है। अब हमारा ध्यान एशियन गेम्स पर है। मुझे टीम के हर खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ पर गर्व है।' पहले विकल्प में ACC के डिप्टी चेयरमैन खालिद अल जरूनी को ट्रॉफी देने का प्रस्ताव था। दूसरे विकल्प में हाल की परंपरा के अनुसार विजेता बोर्ड के प्रतिनिधि से ट्रॉफी दिलाने की बात कही गई थी। नकवी को दोनों विकल्प मंजूर नहीं थे। भारत Vs श्रीलंका मैच के टॉप मोमेंट्स-रिवाइव्ड श्रीलंकाई फील्डर चोट के

मोहसिन नकवी ने सिर्फ श्रीलंका टीम को मेडल दिए

भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया। नकवी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में घेव पर पहुंच गए थे। उन्होंने श्रीलंकाई टीम को मेडल दिए और कप्तान घमारी अट्टाफु को स्मर-अप वेंक भी दिया। बाद में प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया गया।

भारतीय खिलाड़ियों ने पानी की बोतल के साथ जश्न मनाया

भारतीय महिला टीम ने एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी की जगह पानी की बोतल के साथ जश्न मनाया। टीम ने प्रेजेंटेशन के दौरान ACC चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इसके बाद गुग फोटो के दौरान टीम मैचर्स ने कप्तान हरमन्धीत कौर को हाथ में फेड़ों पानी की बोतल ट्रॉफी की तरह उठाने के लिए कहा। हरमन्धीत ने भी मजाकिया अंदाज में बोतल उठाकर जीत का जश्न मनाया।

बाद स्ट्रेचर पर बाहर गई भारतीय पारी के पांचवें ओवर में शो फैकने के दौरान श्रीलंकाई फील्डर विश्वमी गुणरत्ने का दायां टखना बुरी तरह मुड़ गया। वे दर्द से कराहते हुए मैदान पर गिर पड़ीं। इसके बाद फिजियो को बुलाया गया। जांच के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। इस बीच खेल रुका रहा। हालांकि वे दूसरी पाटी में

बल्लेबाजी के लिए उतरीं। उन्होंने 20 रन बनाए। स्मृति सिंगल लेने के चक्कर में रनआउट हुईं। 14वें ओवर में स्मृति सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो गईं। हरमन्धीत कौर के कट शॉट पर दोनों बैटर्स ने रन चुपने की कोशिश की। इस बीच पॉइंट से कबीरा दिलशारी ने शो किया और विकेटकोपर ने गिल्लियां बिखेर दीं।

आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में धीरज बोम्मादेवरा को गोल्ड



क्वार्टर-फाइनल और सेमीफाइनल में भी दर्ज की बड़ी जीत

विश्व रेफिंग में 10वें स्थान पर मौजूद धीरज ने क्वार्टर-फाइनल में तुर्की के बर्किम टसुमर को सीधे सेटों में 7-1 से हराया। इसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने रिखे ऑर्तेगुए के रजत पदक विजेता फ्रांस के ज्यो-वॉल्स वेलांडोट को 7-1 से शिकस्त दी।

एजेंसी

नई दिल्ली। आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के धीरज बोम्मादेवरा ने गोल्ड मेडल जीता। विचार को हुए मुकाबले में धीरज ने जापान के नाकानिशि जुन्या को हराया। पांच सेट तक चले मुकाबले में दोनों का स्कोर 5-5 से बराबर रहा। इसके बाद शूट-ऑफ में धीरज ने परफेक्ट 10 का निशान लगाया, जबकि जुन्या 9 अंक ही हासिल कर सके। शूट-ऑफ में एक-एक तीर चलाने का मौका दिया जाता है। ज्यादा पॉइंट हासिल करने वाला विजेता होता है। धीरज आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाले भारत के दूसरे तीरंदाज बन गए हैं। उनसे पहले डोला नानाजी ने 2007 में दुबई में विमेंस इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट का खिताब जीता था। दो बार पिछड़ने के बाद की वापसी जुन्या ने मुकाबले की शुरुआत शानदार तरीके से की और 3-1 की बढ़त बना ली। धीरज ने तीसरे सेट में 29 अंक हासिल कर स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया। हालांकि, चौथे सेट में जुन्या ने तीनों तीर परफेक्ट लगाकर फिर 5-3 की बढ़त हासिल कर ली। पांचवें सेट में जुन्या 27

अंक ही बना सके, जबकि धीरज ने दबाव में 28 अंक जुटाए। इससे मुकाबला 5-5 की बराबरी पर पहुंच गया। शूट-ऑफ में धीरज ने 10 और जुन्या ने 9 पॉइंट बनाए। धीरज ने मुकाबला 6-5 से अपने नाम किया। धीरज पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे और खिताब जीतने में सफल रहे। इससे पहले 2023 में वह सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गए थे। 2024 में भी वह पदक नहीं जीत सके थे। अंताल्या में जीत से किया था क्वालिफाई धीरज ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित वर्ल्ड स्टेज-3 जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। आठ सदस्यीय एलिट फोल्ड में भारत की ओर से केवल धीरज ही जगह बना सके थे। अब एशियाई खेलों में उतरेगे वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड जीतने के बाद धीरज अब एशियाई खेलों में भारतीय रिकर्व टीम की अगुआई करेंगे। निखली बार हांगझू एशियाई खेलों में उन्होंने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था, जबकि व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर-फाइनल में हार गए थे।

थोक महंगाई अगस्त में बढ़कर 9.92% पहुंची

एजेंसी

नई दिल्ली। अगस्त में थोक महंगाई बढ़कर 9.92% हो गई। जुलाई में यह 9.78% थी। खाने-पीने की चीजें, पशु, गाबर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स महंगे होने की वजह से यह बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार ने आज, 14 सितंबर को ये आंकड़े जारी किए। महंगाई दर 9.92% होने का मतलब यह है कि जो सामान पिछले साल इस समय थोक बाजार में 100 का मूल्य रहा था, वह आज लगभग 109.92 का है। जुलाई 2026 Vs अगस्त 2026 मेजर ग्रुप महंगाई (जुलाई 2026) म हं गा ई (अ ग स्त 2026) म हं गा ई (अ ग स्त 2026) प्राइमरी आर्टिकल्स 8.52% 7.76% पशुएं एंड पावर 20.05% 22.93% मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 8.29%

8.37% खाने-पीने की चीजें भी महंगी आम आदमी को रसोई से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी तेजी आई है। थोक मूल्य सूचकांक में फूड इंडेक्स की हिस्सेदारी 24.99% होनी है। अगस्त 2026 में खाने-पीने की चीजों की थोक महंगाई बढ़कर 7.05% पर पहुंच गई, जो जुलाई में 6.65% थी। प्राइमरी आर्टिकल के तीन मुख्य हिस्से हैं फूड आर्टिकल्स जैसे अनाज, सब्जियां नॉन फूड आर्टिकल में ऑयल सीड आते हैं

चीन ने AI डेवलपमेंट धीमा करने को बताया अमेरिकी चाल

एजेंसी

नई दिल्ली। एंथ्रोपिक के सौईओ डारियो अमोदेई के एआई डेवलपमेंट की रफ्तार धीमी करने के प्रस्ताव को चीन ने 'कोल्ड वॉर प्लेबुक' बताया है। चीनी अखबार ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर एआई की रफ्तार रोकने की मांग अमेरिका के तकनीकी एकाधिकार को बनाए रखने की एक साजिश है। ग्लोबल टाइम्स ने इस कार्टून के जरिए अमेरिका पर निशाना साधा है। कार्टून में अंकल सैम (अमेरिका) को ओपन-सोर्स एआई के रास्ते में ईंट की दीवार बनाते दिखाया गया है, ताकि चीन के बढ़ते दबदबे को रोक जा सके। ग्लोबल टाइम्स ने इस कार्टून के जरिए अमेरिका पर निशाना साधा है। कार्टून में अंकल सैम (अमेरिका) को ओपन-सोर्स एआई के रास्ते में ईंट की दीवार बनाते दिखाया गया है, ताकि चीन के बढ़ते दबदबे को रोक जा सके। डारियो अमोदेई ने चीन पर सख्ती



की मांग की थी डारियो अमोदेई ने एक लेख में एआई बनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इससे एआई से जुड़े खतरों को सगहने और निपटने का समय मिल जाएगा। ओपनएआई के सौईओ सीम ऑल्टमैन और हलीन मस्क ने भी इस बात का समर्थन किया है। डारियो ने अमेरिकी सरकार से मांग की थी कि चीन को रेंजी जाने वाली कंप्यूटर चिप पर और सख्ती की जाए। मॉडल डिस्ट्रिब्यूशन पर भी रोक लगाई जाए। मॉडल डिस्ट्रिब्यूशन का मतलब है कि अमेरिका के महंगे

और एडवॉंस्ड AI मॉडल से सवाल-जवाब का डेटा लेकर कम खर्च और कम समय में अपना नया AI तैयार कर लेना। चीन के कई लेक्स ऐसा कर रहे हैं। डारियो ने एक इंटरव्यू में मांगा कि अगर अमेरिका रफ्तार धीमी करता है और चीन ऐसा नहीं करता, तो यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। चीन बोला- 'ग्लोबल एआई सिस्टम से हमें अलग करने की कोशिश' चीन के सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' ने लिखा कि डारियो अमोदेई का असली मकसद एआई नियमों का बहाना बनाकर चीन के टेक डेवलपमेंट

ट्रम्प बोले- कुछ लोग बेवजह का डर पैदा कर रहे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एआई की ग्रीड कम करने की मांगों को खारिज कर दिया है। ट्रम्प ने कहा कि कुछ लोग बेवजह का डर पैदा कर रहे हैं।

को रोकना है। अखबार ने लिखा, यह एक छिपा हुआ एआई कोल्ड वॉर है। एआई के विकास से चीन को बाहर करने से पूरी दुनिया के लिए नुकसान होगा। ट्रम्प ने कहा, हम एआई के मामले में चीन से आगे हैं। हम दुनिया में सबसे आगे हैं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहता हूं, क्योंकि जो एआई की रेंस जीतगा, वही दुनिया पर राज करेगा। 24 सितंबर को ट्रम्प और शी जिनपिंग की मीटिंग में उठ सकता है मुद्दा अमेरिका और चीनी अधिकारी इसी महीने AI खतरी पर चर्चा करने वाले हैं। 24 सितंबर की समिट में ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी इस मुद्दे पर बात हो सकती है।

वंदे मातरम से शुरू हुआ भारत-अफगान टी-20

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत ने पहले टी-20 में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। रविवार को क्रिकेट में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। टॉस के दौरान श्रेयस अय्यर ने अफगान कप्तान इब्राहिम जादरान को टीम इंडिया की जर्सी दी। भारतीय पेंसर जसप्रीत बुमराह ने टी-20 में 350 विकेट पूरे किए। अभिषेक शर्मा ने 22 बॉल पर फिफ्टी लगाई। उन्होंने 32 गेंद में 82 रन बनाए। अभिषेक ने 12वीं बार 25 या उससे कम बॉल पर फिफ्टी लगाई। मैच में बने 8 मोमेंट्स और रिवाइव्स 28 जनवरी को गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों में कहा गया था कि अगर वंदे मातरम और जन गण मन दोनों गाए जाएं, तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान होना चाहिए। टॉस के दौरान श्रेयस ने अफगान कप्तान को जर्सी दी टॉस के समय भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान को टीम



पहली बार क्रिकेट में वंदे मातरम गाया गया

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच से पहले वंदे मातरम गाया गया और उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन हुआ। भारतीय क्रिकेट में ऐसा पहली बार देखने को मिला।

बुमराह ने 350 विकेट पूरे किए

जसप्रीत बुमराह ने टी-20 क्रिकेट में 350 विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने मैच के पहले ही ओवर में रहमनुल्लाह मुख्तार को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की। बुमराह टी-20 में 350 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं। उनसे पहले युवराज चहल और भुवनेश्वर कुमार यह फासनामा कर चुके हैं।

इंडिया की जर्सी दी। इसी समय 3 मैचों की टी-20 सीरीज की ट्रॉफी और टॉस का सिक्का भी कैमरे पर दिखाया गया। इस सीरीज की खास बात यह है कि मैच भारत में होने के बावजूद अफगानिस्तान टीम होस्ट है। 4. उमरजई ने 64 रन बनाए, अफगान बैटर का भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर अजमतुल्लाह उमरजई ने 64 रन की पारी खेली। उनका यह स्कोर भारत के खिलाफ किसी अफगान बल्लेबाज का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा टी-20 स्कोर है।

और 6-2 से सेट जीतकर US ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। ज्वेरेव इस्ते पहले 2020 में US ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। तब वह दो सेट की बढ़त लेने के बावजूद डेमिनिक थीम से हार गए थे। इस बार उन्होंने उस हार को पीछे छोड़ते हुए बेन शेल्टन को हराकर अपना पहला US ओपन

पाकिस्तान के 11 WTC पॉइंट्स कटे



एजेंसी

इंग्लैंड। खिलाफ टेस्ट सीरीज में स्लो ओवर रेट के लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई है। एग्जिस्टन में खेले गए आखिरी टेस्ट में टीम के 11 WTC पॉइंट्स कटे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया

गया है। पाकिस्तान चह टेस्ट 8 विकेट से हार गया था।एग्जिस्टन टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान ने 89 ओवर गेंदबाजी की थी। समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद टीम को 11 ओवर कम पाया गया, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। WTC पॉइंट और जुर्माना पाकिस्तान का WTC की मौजूदा

साइकल में हर कम ओवर के लिए एक WTC पॉइंट काटा गया है। यह कार्रवाई ICC WTC की प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 16.11.2 के तहत की गई है। वहाँ, खिलाड़ियों पर हर कम ओवर के लिए मैच फीस का 5% जुर्माना लगाया गया है। यह ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22

हर घंटे कम से कम 15 ओवर फैकने होते हैं

ICC के नियमों के मुताबिक, टेस्ट मैच में गेंदबाजी करने वाली टीम को हर घंटे कम से कम 15 ओवर फैकने होते हैं। यानी एक दिन के खेल में आमतौर पर 90 ओवर पूरे करने का लक्ष्य रहता है। अगर टीम तब सक्षम है जरूरी ओवर पूरे नहीं करती है तो उसके खिलाफ स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, ओवर रेट की गणना करते समय अपवाह कुछ परिस्थितियों में टीम को समय की छूट देते हैं।

पाकिस्तान 3-0 से सीरीज हारा

इंग्लैंड दौर पर गए पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार मिली। टीम को पहले मैच में इंग्लैंड ने पारी और 103 रन से हराया। दूसरे मैच में 194 और तीसरे में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी।

के तहत हुआ है। हालांकि, नियमों के मुताबिक किसी खिलाड़ी पर एक मैच के लिए अधिकतम 50% मैच फीस का ही जुर्माना लगाया जा सकता है। पाकिस्तान 11 ओवर कम रहा, इसलिए 5% प्रति ओवर के हिसाब से जुर्माना 55% बनता था। लेकिन अधिकतम सीमा 50% होने के कारण खिलाड़ियों पर 50% मैच फीस का ही जुर्माना लगाया गया। WTC फाइनल की रेंस से बाहर

पाकिस्तान पहले ही WTC पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे था। अब 4 सीरीज में 9 टेस्ट के बाद उसका पॉइंट्स परसेंटेज 4.63 हो गया है। इससे पाकिस्तान की WTC फाइनल में पहुंचने की बची हुई उम्मीद भी खत्म हो गई है। पाकिस्तान नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज की मेजबानी करेगा। इसके बाद न्यूजीलैंड 2027 में पाकिस्तान का दौरा करेगा।

ज्वेरेव ने पहली बार US ओपन खिताब जीता

एजेंसी

नई दिल्ली। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पहली बार मेंस सिंगल्स का US ओपन खिताब जीता। उन्होंने रविवार को न्यूयॉर्क के आर्थर फिश स्टैडियम में बेन शेल्टन को 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 से हराया। यह इस सीजन में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। मैच खत्म होने के बाद भी खेलने को तैयार थे ज्वेरेव मैच पॉइंट पर बेन शेल्टन का शॉट बाहर चला गया, लेकिन एलेक्जेंडर ज्वेरेव को पता नहीं चला कि वह जीत गए हैं। वह अगले पॉइंट के लिए तैयार खड़े थे। स्टैंड में दर्शकों की तालियां गुंजन लगीं, तब उन्हें समझ आया कि मुकाबला खत्म हो चुका है। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर



शेल्टन ने तीसरे सेट में वापसी की ज्वेरेव ने फाइनल की शुरुआत अच्छी की और पहला सेट 6-3 से जीत लिया। दूसरे सेट में शेल्टन ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन ज्वेरेव ने टाइब्रेकर 7-2 से जीतकर बढ़त 2-0 कर ली। शेल्टन ने तीसरा सेट 7-5 से जीतकर वापसी की कोशिश की। हालांकि, ज्वेरेव ने चौथे सेट में

और 6-2 से सेट जीतकर US ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। ज्वेरेव इस्ते पहले 2020 में US ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। तब वह दो सेट की बढ़त लेने के बावजूद डेमिनिक थीम से हार गए थे। इस बार उन्होंने उस हार को पीछे छोड़ते हुए बेन शेल्टन को हराकर अपना पहला US ओपन

ज्वेरेव ने छह साल बाद US ओपन के फाइनल में जगह बनाई

जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने छह साल बाद US ओपन के फाइनल में जगह बनाई। शुरुआती दो राउंड में पांच सेट के मुकाबले खेलने के बावजूद उन्होंने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। सेमीफाइनल में उन्होंने करेन खानावोव को 6-3, 7-6, 7-6 से हराया।

शेल्टन पहली बार US ओपन के फाइनल में पहुंचे

बेन शेल्टन पहली बार US ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कार्लोस अल्वेराज को पांच सेट में हराकर बड़ा उलटफेर किया। यह मुकाबला सुबह 3:33 बजे खत्म हुआ था।

सेमीफाइनल में हमवतन फ्रांसिस खिलाड़ी बनने का उनका सपना अधूरा रह गया। अमेरिकी पुरुष टेनिस का यह इंतजार अब भी जारी है। ज्वेरेव ने शेल्टन की गलफिंड को बताया 'लकी चार' शेल्टन की गलफिंड और अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी ट्रिनिटी रोडमैन भी फाइनल

जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष खिलाड़ी बनने का उनका सपना अधूरा रह गया। अमेरिकी पुरुष टेनिस का यह इंतजार अब भी जारी है। ज्वेरेव ने शेल्टन की गलफिंड को बताया 'लकी चार' शेल्टन की गलफिंड और अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी ट्रिनिटी रोडमैन भी फाइनल

श्रीलंका के रुनेश पाथिराने ने 91.09 मीटर गाला फेंका

एजेंसी

श्रीलंका। जेवलिन थ्रोअर रुनेश पाथिराने ने वर्ल्ड एथलेटिक्स ओलंपिड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। रविवार को बुडापेस्ट में आयोजित चैंपियनशिप में उन्होंने 91.09 मीटर का शो किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.18 मीटर के शो के साथ दूसरे और जर्मनी के जूलियन वेबर 85.89 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पाकिस्तान के ओलिंपिक चैंपियन अश्रिद नदीम 81.49 मीटर के सोबान बेस्ट शो के साथ पांचवें स्थान पर रहे। तीसरे प्रयास में फाइनल में पहुंचे पाथिराने पाथिराने ने तीसरे प्रयास में 87.11 मीटर का शो कर फाइनल राउंड में जगह बनाई। इससे पहले उन्होंने पहले प्रयास में 75.89 मीटर और दूसरे में 85.69 मीटर का शो किया था। नए फॉर्मेट के अनुसार, तीन



अरशद नदीम पांचवें स्थान पर

पाकिस्तान के ओलिंपिक चैंपियन अरशद नदीम 81.49 मीटर के सीजन बेस्ट शो के साथ पांचवें स्थान पर रहे। तीसरे प्रयास में उन्होंने 78.63 मीटर का शो किया था, जो उन्होंने 31 जुलाई को ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वालिफिकेशन राउंड में हासिल किया था। वह क्वालिफिकेशन में सातवें स्थान पर रहे थे।

राउंड में पहुंचते हैं। पाथिराने ने तीसरे प्रयास में 87.11 मीटर का शो कर टॉप-4 में जगह बनाई। इस सीजन में 12 में से 11 में जीते पाथिराने का अब तक 12 ट्रॉफी में से 11 में जीत दर्ज की है। इससे पहले गेम्स में उन्होंने 92.62 मीटर का शो फेंका था, जबकि ज्यूरिख में 92.07 मीटर की

